● वर्ष-4
● अंक-09
रायपुर, बुधवार
21 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› हर लड़की को सीखनी चाहिए...

'लेटरल एंट्री' भर्ती रद्द

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री में आरक्षण सिद्धांतों को लागू करके बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हृश्वश्वज्ञ, सैनिक स्कूल और कई अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के सिद्धांत लागू हों। वैष्णव ने एएनआई से कहा, पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि बाबासाहेब अंबेडकर के पांच पवित्र स्थलों को उनका उचित दर्जा दिया जाए। हमें इस बात पर भी गर्व है कि भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संतृप्ति के सिद्धांतों के तहत, जिसका उद्देश्य हर कल्याणकारी कार्यक्रम को समाज के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों तक पहुंचाना है, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को सबसे अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के फैसलों में आरक्षण के सिद्धांतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वित्त सचिवों को लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्त किया गया था और आरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया लेटरल एंट्री रूट के माध्यम से सेवा में आए थे। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी यूपीएससी के माध्यम से पार्श्व प्रवेश को पारदर्शिता लाने के साधन के रूप में देखते थे और आरक्षण के सिद्धांत को शामिल करके, यह अब स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लेटरल एंट्री का मामला संज्ञान में आने के बाद से ही मैं विभिन्न विभागों से चर्चा कर रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें और गठबंधन में बनी विपक्षी सरकारों ने लैटरल एंट्री की है...विपक्ष यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यह पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। मैं और लोजपा (रामविलास) इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं...

सरकार को 'लेटरल एंट्री' भर्ती रद्द करनी पड़ीः खड़गे

मुंबई । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि केंद्र सरकार को मजबूत विपक्ष के विरोध के कारण 'लेटरल एंट्री' के जरिये की जाने वाली भर्ती को रद्द करनी पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में खरगे ने दावा किया कि अगर नरेन्द्र मोदी सरकार के पास बहुमत होता तो वह आरक्षण लागू किए बिना ही सरकारी पदों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लोगों को भर देती। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''हाल में उन्होंने लेटरल एंट्री से भर्ती की शुरुआत की। उन्होंने संयुक्त सचिव (रैंक के अधिकारियों) की नियुक्ति करने की कोशिश की...लेकिन मैंने सुना है कि लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया वापस ले ली गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष मजबूत है।'' संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मंगलवार को केंद्र के अनुरोध पर नौकरशाही में 'लेटरल एंट्री' भर्ती के लिए जारी अपना नवीनतम विज्ञापन रद्द कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा 'लेटरल एंट्री' भर्ती का विरोध किए जाने के बीच आयोग ने यह कदम उठाया है। यूपीएससी 'लेटरल एंट्री' के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करता है, जिन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की तैनाती होती है। इसमें निजी क्षेत्रों से अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में सीधे संयुक्त सचिव और निदेशक व उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

विधायक देवेन्द्र बलौदाबाजार घटना के जिम्मेदारः दयालदास

मंत्री का आरोप- सोची-समझी साजिश के तहत यादव भिलाई से असामाजिक और शरारती तत्वों को भी अपने साथ ले गए थे

रायपुर। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने आज न्यू सर्किट हाउस रायपुर में बलौदाबाजार की घटना के संदर्भ में भिलाई नगर के कांग्रेसी विधायक देवेन्द्र यादव के अपराधिक कृत्यों एवं उक्त घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में प्रेसवार्ता ली। उन्होंने बलौदाबाजार में 10 जून की घटना के लिए भिलाई नगर के विधायक देवेन्द्र यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सतनामी समाज की असहमति के बावजूद भी वह जबरन सतनामी समाज के आयोजन में पहुंचे। यादव भिलाई से बहुत से असामाजिक और शरारती तत्वों को भी अपने साथ ले गए थे। उन्होंने लोगों को बलौदाबाजार कलेक्टोरेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव और वहां तोड़-फोड़ आगजनी के लिए उकसाया। यादव के साथ गये असामाजिक तत्वों ने भी इस घटना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई।

प्रेसवार्ता के पूर्व में मीडिया प्रतिनिधियों को वीडियो फुटेज भी दिखाया गया, जिसमें विधायक यादव प्रमुखता से लोगों को भड़काते नजर आए। मंत्री बघेल ने आगे कहा कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक संगीन प्रकरण में गिरफ्तारी के बावजूद किस तरह आदतन अपराधी की तरह से विधायक देवेन्द्र यादव व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। किस तरह वे सतनाम समाज के पवित्र झंडे को अपने पावों पर रख रहे हैं। इस तरह आप इनकी मंशा को समझ सकते हैं।

पिछले 10 जून को बलौदाबाजार में हुई घटना बेहद ही दुखद है। वास्तव में एक शांतिपूर्ण आन्दोलन को भड़का कर उसे हिंसक बना देना कांग्रेस के टूलकिट का हिस्सा था। यहां तक कि अमर गुफा की घटना भी इनके टूल किट का ही हिस्सा था। प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं हो रही है या साजिश रची जा रही है। कांग्रेस जहां भी कमजोर होती है या सत्ता में नहीं होती है वहां वह अराजकता पैदा करती है, देश भर में अलग-अलग बहानों से उपद्रव फैलाते रहने की ही एक कड़ी बलौदाबाजार की हिंसा भी थी जिसके टूल कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव हैं।

एक सोची-समझी साजिश के तहत बिना बुलाये कांग्रेस विधायक भिलाई नगर से बलौदाबाजार पहुंचे, उन्हें मंच पर समाज के लोगों ने चढ़ने भी नहीं दिया, फिर भी वे नीचे बैठ कर दंगे के साजिश को अंजाम दिया। आखिर समाज के बैठक में भिलाई नगर के विधायक का क्या काम हो सकता था भला? आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कांगेस के भी अन्य अनेक विधायक वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन देवेन्द्र यादव वहां फसाद कराने भिलाई से पहुंच गए। बलौदाबाजार और भाटापारा के कांग्रेस विधायक भी वहां नहीं पहुंचे थे लेकिन कांग्रेस के टूल के रूप में देवेन्द्र यादव पहुंच गए।

बुलावे के बिना कार्यक्रम स्थल पर जा कर अपने समर्थकों को भड़का कर व्यापक आगजनी एवं तोड़फोड़ किया गया। यादव ने 10 जून को अपने समर्थकों को उत्प्रेरित कर कानून को अपने हाथ में लेने का षड्यंत्र किया, जिससे करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ और सैकड़ों वाहनों को तोडफोड कर आगजनी किया गया। शासकीय भवनों तक को जला दिया गया। आपराधिक कृत्यों में जुड़े रहने का यह यादव का पहला मामला भी नहीं है, ये आदतन अपराधी रहे हैं। इससे पहले ईडी द्वारा कोल घोटाले में देवेन्द्र यादव को चार्टशीट किया गया है तथा उच्च न्यायालय में इस प्रकरण में देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है।

देवेन्द्र यादव के विरूद्ध आधे दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कुछ प्रकरण तो इतने संगीन हैं कि कांग्रेस की भूपेश सरकार भी चाह कर भी यादव के प्रकरण को वापस नहीं ले पायी। ऐसे आपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्ति को आगे कर कांग्रेस वास्तव में प्रदेश में आग लगाने की साजिश रच रही है, इसका खुलासा होना ही चाहिए। न्यायालय एवं कानून की भी अवमानना करना इनके चरित्र का हिस्सा है। कोल घोटाले समेत अनेक मामले में ये न्यायालय के समंस एवं वारंट के तामीली से हर तरह के हथकंडे अपनाकर बचते आ रहे हैं। ये कोयला एवं एवं महादेव ऐप घोटाले में भी अभियुक्त हैं।

कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव के खिलाफ ज्यादातर दर्ज मामले बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ एवं लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा शासकीय सेवकों पर हमलना करने वाले ही हैं। 10 जून को बलौदाबाजार में अपराध में भी इसी तरह के अपराध में विधायक देवेन्द्र यादव की संलिप्तता प्रमाणित हुई है।

देवेन्द्र यादव को बलौदाबाजार मामले में लगातार नोटिस दिये जाने के बाद भी ना ही कभी उपस्थित हुए और ना ही जांच में सहयोग किया। विधायक यादव राहत पाने माननीय हाई कोर्ट भी गए लेकिन वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। विधायक देवेन्द्र यादव द्वारा बलौदाबाजार के प्रकरण में गवाहों को धमकाने का भी प्रयास कर विवेचना को बाधित किया गया। कांग्रेस हमेशा से एससी समाज की विरोधी रही है। भूपेश बघेल के शासनकाल में समाज के लोगों में इतना आक्रोश था कि समाज के युवाओं को नग्न प्रदर्शन तक करने को मजबूर होना पड़ा था। कांग्रेस इस समाज अपमानित करने, और इन्हें उकसा कर राजनीतिक राटा सेंकने के लिए यह साजिश रच रही है। समाज की मांग पर न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। तय समय- सीमा में आयोग अपनी रिपोर्ट सौपेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

पूर्व विधायक सनम जांगड़े जी की अगुआई में एक टीम बनी थी, उस टीम ने सिफारिश की है कि समाज के अनेक ऐसे लोग कांग्रेस के इस साजिश का शिकार हो गए हैं, वे निर्दोष हैं, उन्हें जांच कर मुक्त करने की कारवाई चल रही है। कांग्रेस को उकसाने की कारवाई से बाज आते हुए समाज और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। दोषी चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे छोड़ा नहीं जायेगा। जिस तरह की संवेदनशीलता, परिपक्वता और धैर्य का परिचय इस समाज ने दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाय, कम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार कांग्रेस के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी के तैल चित्र पर आज उनकी जयंती के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, सांसद श्रीमति ज्योत्सना महंत एवम माननीय विधायकगण द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्व. श्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की ।

हरियाणा में चुनावों से पहले कांग्रेस में पड़ी फूट

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के तारीखों की हरियाणा में घोषणा हो गई है। जिसको लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। कांग्रेस जहां राज्य में 10 सालों का अपना वनवास खत्म करके सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं, दूसरी ओर भाजपा लगातार तीसरी बार यह चुनाव जीतकर हरियाणा की कुर्सी अपने पास ही रखना चाहती है। इस बीच हरियाणा समेत पूरे देश की जनता की नजरें कुछ खास नेताओं पर टिकी हैं। जैसे, हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार और पांच बार की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार हैं।

प्रमुख समाचार

मंकीपॉक्स के उपचार के लिए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने संदिग्ध मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) के लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख चिकित्सा संस्थान ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें एम्स के आपातकालीन विभाग में मंकीपॉक्स के मामलों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों का विवरण दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसने पिछले सप्ताह एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, ने कहा कि यह कोई दूसरा कोविड-19 नहीं है, क्योंकि इस वायरस और इसे नियंत्रित करने के साधनों के बारे में पहले से ही बहुत कुछ ज्ञात है। एम्स ने कहा कि बुखार, दाने या मंकीपॉक्स के पुष्ट मामलों के संपर्क में आने वाले रोगियों को तत्काल मूल्यांकन के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए। चिकित्सकों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजे हुए निम्फ नोड्स, ठंड लगना, थकावट और त्वचा के विशिष्ट घावों जैसे प्रमुख लक्षणों की पहचान करने के लिए कहा गया है।

ममता ने किया शुरू रात के साथी प्रोग्राम, छिड़ गया विवाद

कोलकाता। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पतालों में महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए 17 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, महिलाओं के लिए रात की पाली को कम करने के दिशानिर्देशों में से एक की तीखी आलोचना हुई है। महिलाओं के लिए काम करने वाले एक सामाजिक संगठन ने इस दिशानिर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह महिलाओं के प्रति उसी प्रतिगामी रवैये पर आधारित है जिससे स्पष्ट रूप से लड़ने के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि जब हिंसा का स्रोत कार्यस्थल ही है तो महिलाओं को कार्यस्थल या कार्यबल से क्यों हटाया जाना चाहिए? महिलाओं के लिए काम करने वाले एक अन्य संगठन ने कहा कि दिशानिर्देश अदूरदर्शी, प्रतिगामी और हानिकारक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि महिलाएं राज्य में कहीं भी सुरक्षित और सम्मान के साथ काम कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं, गिग श्रमिकों, महिलाओं को रात के दौरान विभिन्न व्यवसायों में काम करना पड़ता है।

शेख हसीना और 23 अन्य के खिलाफ एक और शिकायत

ढाका। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मंगलवार को एक नयी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 23 अन्य पर मई 2013 में एक इस्लामी समूह द्वारा आयोजित रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। 'द डेली स्टार' अखबार की खबर के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के वकील गाजी एमएच तमीम ने हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव (शिक्षा और कानून) मुफ्ती हारुन इजहार चौधरी की ओर से शिकायत दर्ज कराई है। अखबार ने जांच एजेंसी के उप निदेशक (प्रशासन) अताउर रहमान के हवाले से कहा, ''हमने शिकायत दर्ज कर ली है और आज से जांच शुरू कर दी गई है।'' उन्होंने कहा, ''जब हम प्रारंभिक जांच पूरी कर लेंगे और घटनास्थल का मौका मुआयना करेंगे और जब न्यायाधिकरण का पुनर्गठन हो जाएगा तो हम अभियोजन पक्ष के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अपील करेंगे।'' शिकायत में हसीना और 23 अन्य पर पांच मई 2013 को मोतीझील के शापला छतर में हिफाजत-ए-इस्लाम रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है।

अखिलेश यादव गांधी परिवार का दरबारीः केशव मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग लगातर चलती रहती है। यूपी की राजनीति में दोनों नेता अक्सर एक-दूसरे पर हमलावर रहते हैं। हाल में ही केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर निशाना साधा था। इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री ने इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम तक ले लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। दरअसल, अखिलेश ने लिखा था कि कोई 'उप' डबल हार के 'उपहार' के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा-प्रमाणपत्र बाँट रहे हैं। उन्होंन कहा था कि अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो दो 'उप मुख्यमंत्री' की क्या ज़रूरत पड़ती।

राज्यसभा चुनावः भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची

नई दिल्ली। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। वहीं राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली किरण चौधरी भी हरियाणा से राज्यसभा की उम्मीदवार होगी। राज्यसभा चुनाव 3 सितंबर को होने हैं। भाजपा के उम्मीदवारों की बात करें तो असम से मिशन रंजन दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार से मनन कुमार मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार के एक और सीट से भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को टिकट दिया गया है जबकि उड़ीसा से ममता मोहंता भाजपा की उम्मीदवार होंगी। त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्यजी भाजपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नौ राज्यों की 12 रिक्त राज्यसभा सीट के लिए तीन सितंबर को चुनाव होगा।

आज वजूद बचाने के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष

हरियाणा की राजनीति में हीरो से जीरो हुआ चौटाला परिवार

नई दिल्ली। हमने बचपन से हमेशा पढ़ा है कि एकजुटता में बल होता है। राजनीति में भी एकजुटता की वजह से कई पार्टियों की किस्मत अच्छी हो जाती है। वहीं फुट की वजह से पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच हरियाणा के सबसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों में से एक चौटाला परिवार की राजनीतिक इतिहास जबरदस्त रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की पार्टी रही है। हालांकि परिवार में फूट के बाद पार्टी में भी बिखराव हुआ। आईएनएलडी का नेतृत्व 89 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला कर रहे हैं। जबकि इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी की कमान ओमप्रकाश के बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला के हाथों में है।

चौटाला परिवार की राजनीतिक इतिहास को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं देवीलाल का नाम सामने आता है। देवीलाल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और जाट नेता रहे हैं। वर्तमान में इनेलो के संरक्षक और देवीलाल के बेटे ओमप्रकाश सात बार विधायक रह चुके हैं और पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। अभय और अजय चौटाला का भी राजनीतिक इतिहास काफी पुराना है। लेकिन वर्तमान में देखें तो इनेलो और जेजेपी दोनों ही राज्य में अपनी राजनीतिक विरासत को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा के उदय के साथ ही राज्य में इनेलो कमजोर पड़ती गयी। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जबकि इनेलो तब सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी। वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट हुई थी।

जेजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद और राज्य में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में वहां गठबंधन की सरकार बनती है। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बनी सरकार में दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सभी को हैरान करते हुए जेजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया और खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि उसके बाद से जेजेपी भी लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। पार्टी के पास 10 विधायक थे। लेकिन वर्तमान में सिर्फ तीन विधायक ही बचे हुए हैं। पार्टी के बाकी विधायक या तो भाजपा में या कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश में है या हो चुके हैं।

दुष्यंत का दावा है कि इन नेताओं के जाने से वे बेफिक्र हैं। वे कहते हैं, जेजेपी चौधरी देवीलाल की नर्सरी है। लोग यहां आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, पद संभालते हैं और फिर संघर्ष के समय चले जाते हैं।%% पिछली बार चौटाला परिवार ने आईएनएलडी के तत्वावधान में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था

और हरियाणा चुनाव में प्रभाव डाला था। यह 2009 का चुनाव था, जब पार्टी को 25.79त्न वोट शेयर के साथ 31 सीटें मिली थीं। उस समय ओम प्रकाश विपक्ष के नेता थे, जबकि 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से फिर से सरकार बनाई थी। तब भाजपा सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। 2014 में जब भाजपा नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में सत्ता में आई तो पार्टी ने हरियाणा में भी इतिहास रच दिया, जहां उसने 47 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।

2014 के विधानसभा चुनावों में भी चौटाला परिवार ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और इनेलो ने 24.1त्न वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिलीं। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल गए ओम प्रकाश की अनुपस्थिति में अभय को एलओपी बनाया गया था। उपमुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत के लगभग साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान, जेजेपी को उम्मीद थी कि वह राज्य में अपना समर्थन आधार बढ़ाने में सक्षम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले किसान आंदोलन के दौरान उन्हें हरियाणा के लोगों के एक वर्ग और अपनी ही पार्टी के नेताओं और विधायकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जेजेपी ने नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भी 19 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सभी की जमानत जब्त हो गई।

2024 के लोकसभा चुनावों में, जेजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि इनेलो ने उनमें से सात सीटों पर चुनाव लड़ा। दोनों ही पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली, भाजपा और कांग्रेस ने पांच-पांच सीटें जीतीं। राज्य में न तो जेजेपी और न ही आईएनएलडी किसी विधानसभा क्षेत्र में आगे चल पाई। जाट बहुल हिसार सीट पर कांग्रेस के जय प्रकाश, जो कभी देवीलाल के समर्थक थे, ने चौटाला परिवार के तीन सदस्यों - देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह (भाजपा) और ओम प्रकाश की पुत्रवधू सुनैना चौटाला (आईएनएलडी) और नैना चौटाला (जेजेपी) को हराया। हालांकि चौटाला परिवार के कई वफादारों का अब भी मानना है कि अगर इनेलो और जेजेपी दोनों एक हो जाएं और एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो वे फिर से राज्य की राजनीति में वापसी कर सकते हैं।

आज बस्तर बंद, आरक्षण में कोटा के विरोध में आदिवासी समाज

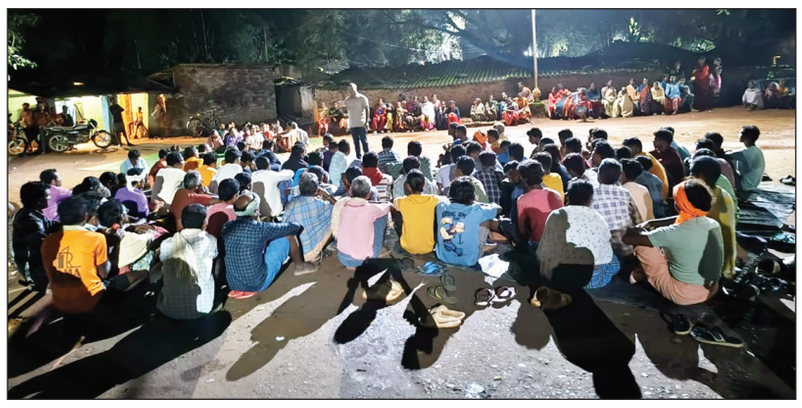

बस्तर। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने की बात भी कही है। कोर्ट के इस फैसले पर बस्तर के आदिवासी और मूल निवासी विरोध में है। एससी के इस फैसले को लेकर 21 अगस्त को बस्तर बंद का आह्वान किया है।

बस्तर में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे का बंद होगा। बंद को लेकर आदिवासी समाज ने बस्तर में बैठकें भी तेज कर दी है। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में बैठक किया जा रहा है। 21 अगस्त को बस्तर के सभी व्यवसायिक संस्थान, परिवहन सेवाएं, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इस दिन जगदलपुर शहर में फैसले के विरोध में रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया जाएगा।

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा और उपवर्गीकरण करते हुए क्रीमीलेयर लागू किया गया है। जिसके विरोध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य मूल निवासियों ने 21 अगस्त को बंद बुलाया है। बंद के साथ ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। संविधान में संशोधन करें या सुप्रीम कोर्ट आदेश को वापस लें। सर्व अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष विक्रम लहरे ने कहा आदिवासी वर्ग आरक्षण के कारण ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फिलहाल 1 या 2 पीढ़ी ही शिक्षा ग्रहण कर पाई है। अब भारत के संविधान में आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया गया है। जिसके खिलाफ भारत बंद किया जाएगा। यह सम्पूर्ण बंद एसटी और एससी के साथ ही पूरे मूलनिवासियों के आव्हान पर किया जा रहा है। महरा समाज के संभागीय अध्यक्ष राजू बघेल ने कहा बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक समानता का अधिकार दिया और भारत के संविधान में आरक्षण लागू किया। यदि आरक्षण के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ किया जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसका पुरजोर विरोध बस्तर संभाग के साथ ही पूरे भारत देश के एसटी, एससी और सम्पूर्ण मूलनिवासी करेंगे।

अतिरिक्त कमरा निर्माण को लेकर धरने पर बैठे विधायक

प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, सैकड़ों लोग हुए शामिल

बालोद। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लाक के ग्राम भरदाकला के उच्चतर माध्यमिक शाला में अव्यवस्था छात्रों को हो रही पढ़ाई में दिक्कत अतिरिक्त कमरे की निर्माण की जल्द मांग को लेकर क्षेत्र के विधायक कुँवर सिंह निषाद ग्रामीणों और छात्रों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की। जिस वजह से अर्जुन्दा से राजनांदगांव मुख्य मार्ग घंटों बाधित रहा।

बता दें कि ग्राम भरदकला के उच्चतर माध्यमिक शाला में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 48 लाख की लागत से 6 अतिरिक्त कमरे बनने है जिस वजह से पुराने कमरो को तोड़ कर नया बनाया जाना है मगर अब तक काम चालू नही हुआ जिस वजह से छात्रों को बैठने में दिक्कत हो रही है वहीं पढ़ाई भी सही नही हो पा रही थी। इसी वजह से विधायक कुँवर सिंह ने एक सप्ताह पहले प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था मगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह हुई की विधायक को सड़क पर बैठना पड़ा। मौके पर पहुचे अधिकारियों द्वारा 6 सितम्बर तक निर्माण प्राम्भ करने का लिखित आश्वासन दिया गया।

छह सितंबर तक का समय

पूरे मामले में विधायक ने कहा कि अगर 6 तारीख तक समस्या हल नही हुई तो 7 तारीख को स्कूल में ताला बन्दी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसके बाद ही विधायक ग्रामीण छात्र इस धरने को समाप्त किये आपको बता दें कि अतिरिक्त कमरे निर्माण को लेकर छात्र-छात्राओं को काफी समस्या हो रही है लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया घन्पुट तक चले इस चक्का जाम के बाद प्रदर्शन को खत्म किया गया अब देखना यह होगा कि दिए गए समय तक यह काम पूरा हो पता है या नहीं।

सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

दुर्ग। दुर्ग छावनी थाना पुलिस ने महिला पुलिस कर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला प्रधान आरक्षक के द्वारा सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने महिला पुलिस कर्मी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज का विवेचना में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, छावनी थाना क्षेत्र के बैकुंठधाम कैंप-2 में महिला पुलिस कर्मी ने दंपति को लाखों का चूना लगाया। दरअसल महिला पुलिस कर्मी ने दंपति से उसकी बेटी को वनरक्षक के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। रुपये लेने के बाद भी बेटी की न तो नौकरी लगी और न ही महिला पुलिस कर्मी ने उनके रुपए लौटाए। जिससे तंग आकर दंपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने इस मामले में महिला पुलिस कर्मी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैंकुंठ नगर कैम्प 2 निवासी के रहने वाले अजय गुप्ता और उसकी पत्नी किरण गुप्ता की जान पहचान दुर्ग पुलिस में कार्यरत महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता से हुई थी। 2 जून 2023 को महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता बैकुंठधाम में रहने वाले अजय गुप्ता के घर पहुंची और उसकी पत्नी किरण गुप्ता से कहा कि आपकी बेटी को वनरक्षक पद पर नौकरी लगवा दूंगी। जिसके लिये उसने दो रुपये मांगे, पीड़ितों ने दो किस्तों में 1 लाख 78 हजार रुपये दिए लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। पीड़ितों ने महिला प्रधान आरक्षक से पैसा वापस करने की मांग की। लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिये। जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बलौदाबाजार सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा

मजदूर की दर्दनाक मौत, हंगामे के बाद हुआ समझौता

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के निजी सीमेंट प्लांट में हादसा हो गया।जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत हो जाने के बाद प्लांट में काम करने वाले मजदूर और मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया। प्लांट के मजदूर उचित मुआवजे की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए।आखिरकार पुलिस ने बीच बचाव के बाद कंपनी प्रबंधन और परिवार के बीच में समझौता कराया।इसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरु की है।

बलौदाबाजार के ग्राम रिसदा में सीमेंट प्लांट है।जिसमें दो दिन पहले ही पोषण यादव नाम का मजदूर काम करने आया था। परिजनों का आरोप है कि मजदूर जब प्लांट के अंदर काम कर रहा था तो जमा हुआ बायक्लोन मजदूर के सिर पर गिरा।जिससे उसे गंभीर चोट आई।चोट आने के बाद दूसरे श्रमिकों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया।जहां उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने परिजनों के साथ हंगामा कर दिया।

मृतक का भाई ईश्वर यादव ने कहा प्लांट के अंदर हादसा हुआ है।सिर पर भारी सामान गिरने से चोट आई।जिससे उसकी मौत हो गई।कंपनी ने 40 साल मुआवजा, क्रिया कर्म के लिए 1 लाख नकद , मुझको माइंस में नौकरी के साथ भाई के ईएआईसी पेंशन देने की बात कही है।

इस बारे में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार झा ने बताया कि घटना सोमवार की रात 11 बजे की हैं। एक मजदूर की मौत हुई हैं, मजदूर का नाम पोषण यादव ग्राम सोनाडीह का रहने वाला था, वह अपने परिवार के साथ ग्राम सोनाडीह में रहता था।मृतक की बॉडी को बलौदाबाजार जिला अस्पताल लाया गया हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही हैं।पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी।

अबूझमाड़ की महिलाओं ने कलेक्टर को भेजी राखी

शाला भवन और आंगनबाड़ी के साथ मांगा पीने का पानी

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ कहे जाने वाले नारायणपुर जिला के ग्राम कुंडोली की महिलाओं ने इस रक्षाबंधन पर कलेक्टर को राखी के साथ पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि आप हमारे बड़े भैया से भी बढ़कर हैं। उन्होंने इसके साथ विश्वास जताया है कि कलेक्टर महोदय उनकी राखी को स्वीकार कर सौगात के तौर पर गांव की बुनियादी समस्याओं का समाधान करेंगे।

गांव की मां अन्नपूर्णा महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर विपिन मांझी को राखी के साथ भेजे पत्र में गांव की बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आदिवासी महिलाओं ने बताया कि उनका गांव जिला मुख्यालय से काफी दूर स्थित है, और यहां तक पहुंचना बहुत कठिन है।

उन्होंने बताया कि गांव में पिछले 14 वर्षों से शाला भवन की कमी के कारण बच्चों को झोपड़ी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसके अलावा गांव में पीने के पानी की भी गंभीर समस्या है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ महिलाओं ने आंगनबाड़ी की सुविधा की भी मांग की है, जो कि बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए अति आवश्यक है।

बता दें कि कुंडोली गांव नक्सल प्रभावित और पहुंचविहीन इलाका है, जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। रक्षाबंधन पर गांव की महिलाओं ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अपने बेटे-बेटियों, याने कलेक्टर से अपने भांजे-भांजियों के लिए शाला भवन, पीने क पानी और आंगनबाड़ी की सुविधा की मांग की है। आदिवासी महिलाओं की यह अनोखी पहल क्या रंग लाती है, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रिमोट को लेकर खूनी संघर्ष चैनल बदलने पर हुआ विवाद

दुर्ग। दुर्ग जिले के शिवपारा इलाके में टीवी चैनल बदलने को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष तक बात पहुंच गई और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 1 शिवपारा में दो दोस्त एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। इसी बीच संतोष ने चैनल बदल दिया जिसके बाद राकेश तिवारी ने संतोष से रिमोट मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे, इस बात से गुस्साए संतोष ने राकेश के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। हमले में घायल राकेश बांधा तालाब के पास कुंदरा में पड़ा था, राकेश की बहन को इसकी सूचना पास ही रहने वाले नारायण चंदेल ने दी। जिसके बाद राकेश को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने यूवक की गंभीर हालत को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया।

एसपी की गाड़ी को नाबालिग ने ठोका

बिलासपुर। त्योहार के दौरान एसपी शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी को नाबालिग कार चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी। उसके बाद वह गाय और महिला को टक्कर मारकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर कार सहित नाबालिग को पकड़ा। वहीं पुलिस ने नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। एसपी रजनेश सिंह इनोवा कार से रक्षाबंधन पर्व में शहर के चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे। उनकी कार रिवरव्यू से निकल रही थी। तभी पीछे से एसेंट कार क्रमांक सीजी 16 सीजे 2902 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए एसपी की इनोवा को टक्कर मार दी। घटना में कार का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद घबराया नाबालिग भागने की फिराक में तेजी से कार चलाते हुए मवेशी और एक महिला को टक्कर मारते हुए शनिचरी की ओर जाने लगा। वहीं एसपी के निर्देश पर चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पीछा करते हुए घेराबंदी कर कार चालक को पकड़ा।

नेशनल हाईवे में शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोमवार की दोपहर कार की ठोकर से एक युवक की मौत हो जाने के बाद गुस्साये ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह शव को सड़क में रखकर चक्काजाम शुरू कर दिया है जिससे एनएच 49 में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे एक बाईक में सवार होकर मयंक दास 14 साल, मेधावी दास 11 साल एवं निखिल दास 21 साल किसी काम के सिलसिले में खरसिया की तरफ जा रहे थे इसी दौरान सामने की तरफ से रहे स्कार्पियो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाईक को जोरदार ठोकर मार दी। जिससे बाईक चला रहे निखिल दास की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी वहीं उसकी बहन मेघावी को गंभीर अवस्था में रायपुर रिफर किया गया है।

भाई को राखी बांधकर घर लौट रही बहन को ट्रेलर ने कुचला

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई को राखी बांधकर पति के साथ ससुराल लौट रही बहन को तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जूटमिल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कांशीचुंआ निवासी मृतका के पति परीक्षित चैहान 46 साल ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह किरोड़ीमल आदर्श भारती हायर सेकेण्डरी स्कूल में कार्यालय सहायक भृत्य के पद में कार्यरत है। कल रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर वह अपनी पत्नी हेमा चैहान 40 साल के साथ शाम को अपनी गांव से बाइक क्रमांक सीजी 13 एच 1495 से बजरंगडीपा जूटमिल अपने रिश्तेदार के यहां राखी बांधकर पत्नी के साथ वापस अपने गांव जा रहे थे। पति-पत्नी जब बाबाधाम तिराहा ट्रांसपोर्ट नगर के पास पहुंचे ही थे कि पीछे की तरफ से आ रहे ट्रेलर ने ठोकर मार दी।

जमीन में सो रही मां-बेटी को जहरीले सांप ने काटा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जहरीले सांप के काटने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, वहीं उसकी मां को अस्पताल मे भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। इस सम्बन्ध मे मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनेकेला निवासी कुमारी पैकरा अपनी 10 साल की मासूम बेटी डालेश्वरी पैकरा के साथ जमीन में सोई थी। देर रात मासूम बच्ची और उसकी मां को जहरीले साँप के काटने के बाद हालत बिगड़ने पर तत्काल लैलूंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मासूम बच्ची की मौत हो गई वहीँ उसकी मां का उपचार जारी है। परिजनों ने सांप काटने से मासूम बच्ची की मौत की सुचना लैलूंगा थाने में दे दी है, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई मे जुट गई।

ओला स्कूटर के बार-बार खराब होने से परेशान हुआ युवक

ठेले में निकाली शव यात्रा, गाया गाना, कहा- मुझको सजा दी ओला ने ऐसा क्या गुनाह किया

दुर्ग। सोशल मीडिया में ओला स्कूटर की शव यात्रा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का है। युवक अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से इस कदर परेशान हुआ की उसने स्कूटी को ठेले में रखकर उसकी शव यात्रा निकाल दी। इतना ही नहीं युवक ने इसके लिए लाउडस्पीकर भी लगाया और पीछे-पीछे स्वयं माइक लेकर लोगों से अपील करता रहा कि कभी भूलकर भी ओला की स्कूटी न खरीदें। इस पूरे वाकया को राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, शांतिनगर निवासी सागर सिंह ने लल्लूराम डॉट कॉम को बताया कि एक साल पहले एक लाख पचास हजार रुपये की इलेक्ट्रिक ओला स्कूटी उन्होंने खरीदी थी।

इसका उन्होंने फाइनेंस भी करवाया था। बैंक इंटरेस्ट मिलाकर यह स्कूटी उन्होंने एक लाख 85 हजार रुपये में खरीदी। लेकिन उन्हें उस बात का अंदाजा नहीं था कि यह स्कूटी उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि स्कूटी के बार-बार सर्विसिंग के कारण पिछले एक साल से सागर टेंशन से गुजर रहे हैं, उनका कहना है कि स्कूटी खरीदने के कुछ महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन तीन-चार महीने बाद स्कूटी खराब होने लगी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया, तब उन्होंने खराब सर्विसिंग से परेशान होकर उसकी शव यात्रा निकाल दी। इस वीडियो के वायरल होते ही सागर को कंपनी से फोन आया और स्कूटी बनाकर दी गई लेकिन कुछ दिन बाद स्कूटी फिर खराब हो गई।

सागर का कहना है कि वो जब भी स्कूटी को सर्विस सेंटर लेकर जाते थे तो खराबी ठीक करने में 15-20 दिन का समय लिया जाता था। हर बार पार्ट्स ना होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया जाता था। वहीं कुछ दिन पहले उनकी स्कूटी के अचानक चारों इंडीकेटर जलने लगे और स्कूटी रामनगर के पास अचानक बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद भी जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो उसे धक्का मारकर घर तक लाना पड़ा।

सागर ने कंपनी को सबक सिखाने के लिए अपने घर से स्कूटी को ठेले पर रखा और उस पर फूल माला, गुलाल लगाकर शो रूम तक शव यात्रा निकाली। सागर ने स्कूटी के साथ एक स्पीकर रखा और खुद माइक पर लोगों से अपील करता रहा कि सुबह-शाम खा लेना केला, लेकिन भूलकर भी ना लेना ओला। इसके अलावा युवक ने शोरूम के बाहर खड़े होकर फिल्मी गाने में भी कंपनी की खराब सर्विसिंग पर तंज कसा और गाते हुए कहा कि मुझको सजा दी ओला ने ऐसा क्या गुनाह किया। उसके इस तरह के तंज को देखने के लिए राह चलते लोग रुक कर मोबाइल से वीडियो बनाने लगे।

शराब घोटाले के आरोपियों की याचिकाएं हाई कोर्ट ने की खारिज

■ **दर्ज एफआईआर को दी गई थी चुनौती**

बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के बेंच के फैसले से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर व विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बता दें, कि शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। इन सभी आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अपने खिलाफ की गई एफआइआर को निरस्त करने की मांग की थी।

आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी। इस मामले में बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

संक्षिप्त समाचार

दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह

रायपुर। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। इस कड़ी में पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह 23 अगस्त की शाम को रायपुर पहुंचेंगे। 24 और 25 को बैठक लेने के बाद 25 की शाम को वापस दिल्ली चले जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री शाह नक्सल प्रभावित सात राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ तीन अलग-अलग बैठक लेंगे। इसके साथ ही बैठक में अर्द्धसैनिक बलों के ऑफिसर भी शामिल होंगे। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की जायेगी। उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

विस परिसर के सेन्ट्रल हॉल में स्व. राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर स्थित

सेन्ट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के तैल चित्र पर मंगलवार को उनकी जयंती के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत एवं विधायकगण द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्व. राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 12 अधिकारी बनाए गए ऑब्जर्वर

रायपुर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर बनाया है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 9 आईएएस अफसरों जिनमें हिमशिखर गुप्ता, राजेश सिंह राणा, नरेंद्र कुमार दुग्गा, भीम सिंह, डॉ. प्रियंका शुक्ला, जय प्रकाश मौर्या, संजीव कुमार झा, विनित नंदनवार और ऋतुराज रघुवंशी का नाम शामिल है। इसके अलावातीन आईपीएस अफसरों प्रशांत कुमार अग्रवाल, अभिषेक मीणा, उदय किरण को ऑब्जर्वर के बनाकर यहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। बतादें कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में (18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर) विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा में एक अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना एक साथ चार अक्टूबर को होंगे।

विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग को लेकर यादव समाज ने खोला मोर्चा

बिलासपुर। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर यादव समाज ने विरोध किया है। इस संबंध में मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में जिला यादव समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस ली। इसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध किया गया। यादव समाज के लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव की निशर्त रिहाई की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिला बिलासपुर यादव समाज के अध्यक्ष अमित यादव और संयोजक हीरा यादव ने कहा कि देवेंद्र यादव विघटनकारी तत्वों के साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। सतनामी समाज के आमंत्रण पर बलोदा बाजार जाकर उन्होंने उनके धरना प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर उनके हितों के लिए संघर्ष किया था। उनके वहां से जाने के बाद विघटनकारी तत्वों ने वहां उत्पाद मचाया, जिसमें विधायक देवेंद्र यादव की कोई भूमिका नहीं थी। राजनीतिक विरोधियों के कारण लोगों ने कांग्रेस विधायक को इस केस में फंसा दिया है। यादव समाज के लोगों ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर उन्हें निशर्त रिहा नहीं किया गया तो सभी जिलों में समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज, 7 दिन और हिरासत में रहेंगे

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार तोड़फोड़ और आगजनी केस में गिरफ्तार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की आज न्यायिक रिमांड खत्म होने वाली थी। सुनवाई के लिए देवेंद्र यादव को आज बलौदबाजार कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। सुबह 5 बजे से ही बलौदबाजार पुलिस विधायक के भिलाई स्थित सेक्टर 5 निवास पर पहुंच गई थी। इस

दौरान सैकड़ों विधायक समर्थक भी पहुंचे। जमकर नारेबाजी होने लगी। विधायक ने सोशल मीडिया पर साय सरकार पर आरोप लगाते हुए सतनामी समाज के युवाओं के लिए आगे भी लड़ाई जारी रखने का दावा किया। लगभग शाम 7 बजे देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया।

एमएलए देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ बलौदा बाजार लेकर पहुंची। वहां सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने देवेंद्र यादव को 20 अगस्त तक न्यायिक रिमांड में भेजा। इसके बाद देवेंद्र यादव को रायपुर सेंट्रल जेल लाया गया। आज देवेंद्र यादव की रिमांड अवधि खत्म हो रही है।

10 जून को बलौदाबाजार में सतनामी समुदाय के लोगों ने दशहरा मैदान में रैली निकाली। फिर हजारों की भीड़ कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंच गई। आक्रोशित भीड़ ने बलौदाबाजार एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में आग लगा दी। लगभग 200 से ज्यादा बड़ी और छोटी गाड़ियों को फूंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के बड़े नेता सहित लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैली के सीसीटीवी फुटेज में देवेंद्र यादव के नजर आने के बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से तीन बार नोटिस भेजा गया। देवेंद्र यादव का कहना है कि वो नोटिस के जवाब में बलौदाबाजार पुलिस के सामने पेश हुए थे।

24 को प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन विधायक दल ने बनाई रणनीति

रायपुर। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी मामले को लेकर आज राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें विधायक की गिरफ्तारी का बड़ा विरोध करने रणनीति बनाई गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। बैठक के

बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत अन्य विधायक केंद्रीय जेल पहुंचकर देवेंद्र यादव से मुलाकात की।

बैठक में नेता-प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने विधायकों से चर्चा की। डॉ। महंत ने कहा, सरकार ने गलत तरीके से विधायक को गिरफ्तार कराया है। गिरफ्तारी का कांग्रेस कड़ा विरोध करेगी। सभी विधायक प्रेसवार्ता कर अपना विरोध जताएंगे। 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा।

ट्रांसजेंडर्स ने सीएम विष्णुदेव साय को बांधी राखी

■ **महिलाओं और बच्चों ने भी बिखेरी खुशियां**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को पहली बार किसी ट्रांसजेंडर्स ग्रुप में रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधी।आपको बता दें कि ये पहला मौका था जब प्रदेश के सीएम को किसी ट्रांसजेंडर ने राखी बांधी हो।राखी बांधने के बाद ट्रांसजेंडर्स ने सीएम साय की लंबी उम्र की कामना की।

आपको बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर स्वच्छता दीदियां, दिव्यांग बच्चे और महतारी वंदन योजना की लाभार्थी बहनों ने भी सीएम साय के कलाई में राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों और बच्चियों को उपहार भेंट किए और उनके सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी बच्चियों और बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज मुझे यह अहसास ही नहीं हुआ कि मेरी कोई सगी बहन नहीं है।प्रदेशभर से आई बहनों और बच्चों का स्नेह और मंगलकामनाएं पाकर मैं अभिभूत हूं। हमारी सरकार उनके सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में पहल की है।

विष्णुदेव साय ने कहा महतारी

वंदन योजना के माध्यम में बहनों और माताओं के प्रति अपने इसी दायित्व को पूरा किया है।मुझे संतोष है कि इस योजना में प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों को हर माह एक-एक हजार मिल रहा हैं।महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमने बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। इस योजना के जरिए हर महीने महिला बहनों को मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि महिलाओं और बहनों की सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। उनकी छोटी-मोटी घरेलू जरूरतें इस राशि से पूरी होने लगी है।

रक्षाबंधन के मौके पर सीएम साय ने कहा कि आप सभी बहनों का स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। रक्षाबंधन के इस पर्व पर, मैं आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करता हूं। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में खुशी का माहौल था। बड़ी संख्या में राखी बांधने पहुंची बहनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी एक-दूसरे को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आएं।

छत्तीसगढ़ की बेटी ने कैसे पैर से सीएम साय को लगाया तिलक, चढ़ाए पुष्प और ऐसे बांधी राखी

रायपुर। रक्षाबंधन का पर्व सोमवार को देशभर में हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भी उनकी बहनों ने राखी बांधी। लेकिन उनमें से एक बहन ऐसी थीं जिसके राखी बांधने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धमतरी से आई दिव्यांग बेटी वर्षा ध्रुव ने मुख्यमंत्री को अपने पैरो से न

केवल राखी बांधी बल्कि पैर से तिलक भी लगाया और उन्होंने अपने भाई यानी मुख्यमंत्री को पुष्प भी चढ़ाए। मुख्यमंत्री ने वर्षा को मिठाईयां भेंट की और उसके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी।

महादेव ऑनलाइन सट्टा एप केस में नया मोड़

अब सीबीआई करेगी मामले की जांच!

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ऑनलाइन महादेव सट्टा एप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार मामले की फाइल सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो इस घोटाले में लिप्त आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। क्योंकि इस केस में प्रदेश के कई सीनियर नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 420, आइपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार में पांच साल तक राज्य में सीबीआई के बैन के बाद दिसंबर 2023 में सूबे में सत्ता बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने राज्य में पांच से लगे बैन को हटा दिया था। पांच साल बाद छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने दस्तक दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सीजीपीएससी 2021 की भर्ती में हुई अनिमितता की सीबीआई ने पहली जांच शुरू की है। वहीं बिरनपुर हिंसा मामले की सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है और अब तीसरी जांच महादेव एप घोटाला की भी सीबीआई करेगी।

अक्टूबर 2022 में कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान ईडी ने महादेव सट्टा एप मामले की जांच शुरू की थी। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में पुलिस ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी। इन्हीं केस के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच की फाइल को आगे बढ़ाया था।

महादेव बेटिंग एप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। एप के

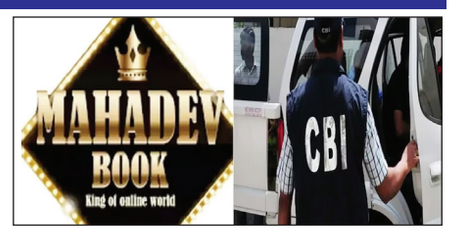

जरिये क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिये एप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस एप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। इस मामले में रणवीर कपूर पर भी अवैध रूप से पैसे बनाने का आरोप लगा है। इसे लेकर ईडी ने कार्रवाई की है।

महादेव बेटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक एप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते थे। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को

सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80त्न हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। इसे ऐसे बनाया गया था कि सिर्फ 30 फीसदी यूजर जीतते, बाकी हार जाते। इस एप के जरिए हुई कमाई को हवाला के जरिए होटल कारोबार और फिल्मों में लगाया गया।

दरअसल, इस एप से जो भी काली कमाई होती थी उसे प्रमोटर बॉलीवुड फिल्मों और होटल के व्यापार में करते थे। धीरे-धीरे रवि और सौरभ की बॉलीवुड हस्तियों से पहचान हो गई। अब बारी आती है दुबई में हुई सौरभ की आलीशान शादी की।

छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले तीन घंटे गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक, बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मारवाही, जांजगीर-चंपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, रायगढ़, राजनांदगांव, सक्ति, सूरजपुर ,सरगुजा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सारंगढ़ ,बिलाईगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक, एक जून 2024 से अब तक राज्य में 806.1 मिमी औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 20 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1740.2 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 440.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 799.1 मिमी, बलरामपुर में 1160.5 मिमी, जशपुर में 648.0 मिमी, कोरिया में 815.9 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 817.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 689.8 मिमी, बलौदाबाजार में 828.5 मिमी, गरियाबंद में 766.3 मिमी, महासमुंद में 580.5 मिमी, धमतरी में 729.1 मिमी, बिलासपुर में 715.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर उच्च न्यायालय की मोहर

उच्च न्यायालय ने माना सबूतों के आधार पर हुई है एफआईआर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार पर *जीरो टॉलरेंस*की नीति पर आज उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है। प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपियों के विरूद्ध ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय में इसके विरूद्ध याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि सबूतों के आधार पर ही ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निदेश पुरोहित, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कराने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विगत 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज

फैसला आया है। उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की थी। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने जिरह किया था। उच्च न्यायालय में छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्ल्यू-एसीबी के खिलाफ दायर थीं। इन याचिकाओं में शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा पुनः की जा रही कार्यवाही और ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्हें खारिज करने की याचना की गई थी। इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा के मुताबिक कांग्रेस सरकार में अनवर ढेबर ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए एपी त्रिपाठी को सीएसएमसीएल (सीएसएमसीएल) का एमडी नियुक्त कराया था। इसके बाद अधिकारी, कारोबारी और राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। एसीबी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। शराब घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने सबसे पहले मई के शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक अनवर ढेबर ने साल 2019 से 2022 तक दो हजार करोड़ रुपए का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया। इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया। ईडी की ओर से यह बड़ी बात कही गई कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बांकी की बड़ी रकम अपने राजनीतिक आकाओं को दी है। इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह को भी पकड़ा गया था। उत्तरप्रदेश एसटीएफ की पूछताछ में अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी ने बताया है कि इस घोटाले की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी शराब निर्माता कंपनियां थीं। नोएडा स्थित विधु की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्युरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को होलोग्राम बनाने का टेंडर मिला था। उसी से डुप्लीकेट होलोग्राम बनाकर डिस्टिलरीज को भेजा जाता था। वहां से अवैध शराब पर इन होलोग्राम को लगाया जाता था। ईडी और ईओडब्ल्यू ने संलिप्त डिस्टिलरीज के संचालकों और उनसे संबंधित लोगों को भी आरोपी बनाया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उच्च न्यायालय के आज के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि नकली होलोग्राम मामले में अब शराब निर्माता कंपनियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।

त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी, रेलवे ने फिर कैंसिल की ट्रेनें

रायपुर। त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने और देरी से चलने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों राजनांदगांव तीसरी रेल लाइन के नान इंटरलाकिंग के चलते 72 ट्रेनें रद हो चुकी हैं। इसके बाद बिलासपुर-कटनी रेल लाइन और दमोह स्टेशन में मेगा ब्?लॉक के चलते 46 ट्रेनें रद कर दी गई। वहीं अब उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में अधोसंरचना विकास के लिए रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द करने समेत 3 के नियंत्रित परिचालन, 2 ट्रेनों को देरी से रवाना और 6 के रुट में परिवर्तन का निर्णय लिया है।

बता दें कि उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में पलवल और न्यू पृथला जंक्शन (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) यार्ड को जोड़ने का कार्य करेगा। यह कार्य 29 अगस्त से 17 सितम्बर तक किया जायेगा इसी कार्य के फलस्वरूप 13 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। लगातार ट्रेनों के रद्द होने व

रुट परिवर्तित करने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुट में जो ट्रेनें चल रही है, वह भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। ऐसे में यात्रियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।

रद्द होने वाली ट्रेनें-

14624 फिरोजपुर-सिवनी एक्सप्रेस, जो 4 से 17 सितंबर तक रद्द रहेगी।

14623 सिवनी-फिरोजपुर एक्सप्रेस, जो 5 से 18 सितंबर तक रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें-

12550 शहीद कैप्टन तुषार महाजन-दुर्ग एक्सप्रेस 29 अगस्त, 5 और 12 सितंबर को आदर्श नगर दिल्ली-दिल्ली कैंट-रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर चलेगी।

18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 से 16 सितंबर के बीच आगरा-मिटावल-खुर्जा-मेरठ शहर होकर रवाना होगी।

18238 अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 से 16 सितंबर के बीच मेरठ शहर-खुर्जा-मिटावल-आगरा होकर रवाना होगी।

18477 पूरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 4 से 15 सितंबर के बीच आगरा-मिटावल-खुर्जा-मेरठ सिटी होकर चलेगी।

18478 योग नगरी ऋषिकेश-पूरी उत्कल एक्सप्रेस 6 से 17 सितंबर के बीच मेरठ सिटी-खुर्जा-मिटावल-आगरा होकर चलेगी।

20807 विशाखापटनम-अमृतसर एक्सप्रेस 6, 7, 10, 13 और 14 सितंबर को आगरा-मिटावल-गाजियाबाद-नई दिल्ली होकर चलेगी।

नियंत्रित होने वाली ट्रेनें-

12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोडवाना एक्सप्रेस 29 और 31 अगस्त, 2, 3, 4 और 5 सितंबर को असावती रेलवे स्टेशन में 40 मिनट तक नियंत्रित होगी।

17 सितंबर को चलने वाली 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोडवाना एक्सप्रेस 45 मिनट तक असावती स्टेशन पर रोकी जाएगी। 12442 नई दिल्ली-बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस 14 सितंबर को असावती स्टेशन में 45 मिनट तक नियंत्रित होगी।

देरी से रवाना होने वाली ट्रेनें-

12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोडवाना एक्सप्रेस 12 सितंबर को 1 घंटा 30 मिनट की देरी से रवाना होगी।

12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोडवाना एक्सप्रेस 14 और 16 सितंबर को 1 घंटे की देरी से चलेगी।

इन परिवर्तनों से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। त्योहारों के समय यात्रा करने वाले लोग अपने पूर्व निर्धारित यात्रा योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे पैनिक सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने यात्रा की योजना बनाएं और अपडेट्स पर नज़र रखें।

लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश

उमेश चतुर्वेदी

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में हर प्रधानमंत्री द्वारा भावी योजनाओं का खाका पेश किया जाता है तथा अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा इस भाषण के तीन मुद्दों ने। प्रधानमंत्री मोदी 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा जोर-शोर से लगाते रहे हैं और इस विचार से प्रभावित नीतियां भी लागू करते रहे हैं। बाद में इसमें 'सबका विश्वास' और 'सबका प्रयास' भी जुड़ गये। वे जिस भाजपा के नुमाइंदे हैं, उसे हिंदू और हिंदुत्ववादी पार्टी का विशेषण उसके विरोधियों द्वारा मिला है। जब तक नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति के शीर्ष पर नहीं पहुंचे थे, भाजपा की वैचारिकी के लिहाज से माना जाता रहा कि अगर वे सत्ता में आयेंगे, तो उनकी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के लिए खास नहीं होगा। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते मोदी की ऐसी छवि विरोधियों ने सफलतापूर्वक गढ़ी। उन्हें मुस्लिम विरोधी के रूप में ऐसा स्थापित किया गया कि आज भी आम मुस्लिम मतदाता सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के बावजूद मोदी और भाजपा विरोधी है। मोदी ने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिये बड़ी योजनाएं शुरू हुईं। लेकिन कभी भी मुस्लिम समुदाय का ठोस समर्थन भाजपा को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक गांव को लेकर खबरें भी आयीं कि इस मुस्लिम बहुल इस गांव में सैकड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला, पर लोकसभा चुनाव में इस गांव में भाजपा को महज चार-पांच वोट ही मिले। ऐसे अनुभवों के बाद भाजपा के अंदर ही सवाल उठने लगे कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का क्या फायदा! शायद यह दबाव ही है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस नारे का उल्लेख नहीं किया। इसे लेकर कथित सेकुलर राजनीति का परेशान होना स्वाभाविक है। उसे पता है कि वह जितना परेशान दिखेगी, उतना ही उसका अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात रही- 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना और इसके लिए निरंतर काम करना। प्रधानमंत्री के इस मंत्र का मकसद साफ है कि आजादी के सौवें साल में देश विकसित देशों की पांत में आ जाए। भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। विभिन्न क्षेत्रों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी प्रधानमंत्री को लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए उनके इस संदेश को भी गहराई से देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में न्यायिक सुधार की भी बात की। सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून संसद से पास करा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एकतरफा सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। पर जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जताया, उससे साफ है कि वे न्यायिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिये जो कॉलेजियम व्यवस्था है, उस पर खूब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने संकेत दे दिया है कि उसकी जगह वे नयी और ज्यादा तार्किक एवं न्यायोचित व्यवस्था लायेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों में भय का माहौल हो, ताकि जनता को लूटने की उनकी परिपाटी पर लगाम लग सके। उन्होंने जता दिया कि तीसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार विरोधी उनकी मुहिम जारी रहेगी।

भारतीय कृषि का अमृतकाल

शिवराज सिंह चौहान

कृषि विकास और किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख-समृद्धि लाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने छह सूत्रीय रणनीति बनाई है। उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी हैं अच्छे बीज, जो कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन में सक्षम हो सकें। ऐसे बीजों की 109 नई किस्मों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र और किसानों को समर्पित किया है।

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। मुझे अपने कृषि विज्ञानियों पर गर्व है जो जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि में किए जा रहे नवाचारों से कृषि एवं किसान कल्याण सुनिश्चित होगा।

किसान होने के नाते मैं भलीभांति समझता हूं कि बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छे बीज कितने आवश्यक हैं। अगर बीज उन्नत और मिट्टी एवं मौसम की प्रकृति के अनुकूल होंगे तो उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी जी ने यह समझा और व्यापक विजन के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शित किया। विविधता भारतीय कृषि की विशेषता है। यहां कुछ दूरी के अंतराल पर ही खेती का मिजाज बदल जाता है। जैसे मैदानी खेती अलग है तो पहाड़ों की खेती अलग। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की 109 नई किस्में जारी की गई हैं। इनमें खेती की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हैं। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने और श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है।

हमारा संकल्प है कि किसान के परिश्रम का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भारत की चिंता भी रही है कि मानव शरीर और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन हो। आज भारत नई हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता तथा ईंधनदाता भी बन रहे हैं। मोदी जी के प्रयासों से खेती के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, फूलों-फलों की खेती सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है।

पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकता में कृषि और किसान रहे ही नहीं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार 663 करोड़ रुपये था जो 2024-25 में बढ़कर 1 लाख 32 हजार 470 करोड़ रुपये हो गया है। यह बजट सिर्फ कृषि विभाग का है। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग बजट है। मोदी सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2,100 रुपये सब्सिडी जबकि डीएपी के एक बैग पर 1083 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान स्वावलंबी और सशक्त हुआ है। फसलों के नुकसान पर भी फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

मोदी सरकार में किसान को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए। उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। इसी कड़ी में एक लाख करोड़ रुपये की एग्री इन्फ्रा फंड के जरिये कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसान और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिये टेक्नोलाजी से दूरदराज की हमारी माताओं-बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने के पहले चरण में अब तक 35 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मोदी जी का विजन है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 निर्यात केंद्रित बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1500 से अधिक मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही 6,800 करोड़ रुपये की लागत से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने की भी तैयारी है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल और अन्य उपज के लिए नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि दलहन फसलों में तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

यजुर्वेद में उल्लिखित है %अन्नानां पतये नमः क्षेत्राणां पतये नमः% अर्थात अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी अन्नदाताओं को नमन। कृषि पराशर में भी उल्लेख है - अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है एवं अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। किसानों के बिना इस देश का अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी किसानों को प्रणाम किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आत्मा। हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घकालिक विजन तथा सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी और समग्र विकास वाले सोच के साथ भारत एवं भारतीय कृषि निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई-बहन आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और समृद्ध संपन्न होने के साथ-साथ देश के अन्न भंडार भरते रहेंगे ।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

लक्षण-समन्वय-विवेचन (भाग-4)

गतांक से आगे...

इसलिये जब हम वेदशाखाओं में भी देश काल परिस्थिति के अनुसार अनिवार्य न्यूनाधिक्य पाठ देख पाते हैं तथापि प्रत्येक ग्रन्थ के लिए हमारे हृदय में तथैव श्रद्धा भाव बना रहता है, तो फिर उसी देश काल परिस्थिति के वक्र चक्र को भूल कर पुराणों के अगण्य परिवर्तन को पर्वतायमान करके दिखाने का उपहासास्पद प्रयत्न क्यों किया जाता है - यह हमारी समझ में नहीं आता।

इस प्रसंग में यह बता देना अनावश्यक न होगा कि आज से पांच हजार वर्ष पूर्व श्री वेदव्यास जी ने अपने नाम को अन्वर्थ करते हुये गुरु शिष्य परम्परागत वेदमन्त्रों का याथातथ्येन स्वरूप स्थिर किया था और उसी समय पुराणों का भी संकलन किया था। पाठ-व्यत्यय की व्यवस्था इससे पूर्वकाल में कैसी थी इसका तो अनुमान करना भी मनुष्य बुद्धि से बाहर है तथापि यह मानने में किसी भी सत्यप्रिय को आनाकानी नहीं हो सकती कि इस समय जो पाठों की न्यूनता वा अधिकता मिलती है वह वेदों और पुराणों दोनों में ही पाँच हजार वर्ष से इधर की है। चार्वाक, बौद्ध, जैन और खासकर यवन काल में धर्मान्धता से वेदों और पुराणों का मूलनाश करने के लिये जो जघन्य प्रयत्न वर्ताव में लाये गए हैं उनका प्रभाव प्रायः सभी हिन्दू साहित्य पर पड़ा है। उस में भी पुराण तो सदा से कथाप्रसङ्गों द्वारा सार्वजनीन से रहे हैं, अतः उनमें वक्ताओं के बाहुल्य के कारण मनुष्य-बुद्धिसुलभ फेरफार का हो जाना अधिक सम्भव है।

कुछ पश्चात्य समालोचकों ने तथा उनके चर्वितचर्वण में ही चातुर्य की चरम सीमा मानने वाले दयानन्दी लोगों ने पुराणों की पद्य- संख्या गिनने की पद्धति से अनभिज्ञ होने के कारण भारी भूल दिखाई है । अतएव भागवत मत्स्य आदि पूर्ण संख्या-सम्पन्न पुराणों का प्रमाण भी अटकल पच्चू न्यूनाधिक लिख मारा है।

क्रमशः ...

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस

श्वेता

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है ताकि समाज में वृद्ध व्यक्तियों के योगदान की जागरूकता बढ़ाई जा सके। भारत में, वरिष्ठ नागरिक का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसने साठ साल की आयु पूरी की हो। एक और आम अर्थ में, वरिष्ठ नागरिक बुढ़ापे में आने वाले लोग होते हैं, खासकर वे जिन्होंने सेवानिवृत्ति की हो। यह दिन उन वृद्ध व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता, ज्ञान और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, साथ ही उन समस्याओं की जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी जिनका सामना वे करते हैं।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का महत्व दोगुना है। सबसे पहले, यह समाज में वरिष्ठ नागरिकों के योगदान का सम्मान करने का दिन है। वरिष्ठ नागरिकों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परिवारों को बढ़ाने और व्यवसायों के निर्माण से लेकर सेना और अग्रणी सरकारों में सेवा करने तक। उन्होंने अपने ज्ञान को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाया है, जिससे आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसे आकार देने में मदद मिली है।

दूसरा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। यह स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसे संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के भी अपराध और दुर्व्यवहार का शिकार होने की अधिक संभावना है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन नीतियों की वकालत करने का एक अवसर है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार करेंगे।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रयासों से पता लगाई जा सकती है। 1988 में, राष्ट्रपति रीगन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अगस्त को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में घोषणा की। इस दिन का उद्देश्य देश में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित करना था, जबकि कार्यक्रमों और नीतियों के महत्व को भी उजागर करना था जो उनकी भलाई का समर्थन करते हैं।

समय के साथ, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का पालन संयुक्त राज्य अमेरिका से परे विस्तारित हुआ, जो एक वैश्विक उत्सव में विकसित हुआ। दुनिया भर के लोग समाज में वरिष्ठ नागरिकों की अमूल्य भूमिका को पहचानते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने से लेकर युवा पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करने तक। इस मान्यता के कारण विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को एक अंतरराष्ट्रीय पालन के रूप में स्थापित किया गया।

बदले समीकरण मोदी सरकार की लेंगे परीक्षा

शेखर गुप्ता

बांग्लादेश के घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत के पड़ोस को सुर्खियों में ला दिया है। साथ ही ऐसी स्थितियों से निपटने के मोदी सरकार के रिकॉर्ड पर भी सबकी नजर है। आज के हालात पर गहराई से नजर डालने के लिए हमें चौथाई सदी पहले जाना होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की बस यात्रा कर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बड़ी पहल की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने मित्र चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं।

वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और 'पड़ोसी प्रथम' का नारा दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगाई और अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी मुल्कों की यात्रा की। एक बार तो उनकी यात्रा बेहद नाटकीय रही, जब वह बिना किसी को बताए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी में मुबारकबाद देने लाहौर पहुंच गए।

उस समय उम्मीद जगी थी। 25 साल में पहली बार बहुमत की सरकार चला रहे देश का मुखिया अगर ऐसे सात संप्रभु देशों के बीच रिश्तों में सुधार के लिए इतना प्रतिबद्ध है, जिनके बीच कई मतभेद थे तो मतभेदों और टकरावों को दूर कर सभी के बीच सेतु बनाना मुमकिन था। हालांकि इन देशों के बीच कुछ मतभेद विचारधारा के कारण थे, जो समय के साथ गहरे हो गए थे। शीतयुद्ध के दौर के पूर्वग्रह भी इनके बीच थे। इन समस्याओं से निजात पाकर राह बनाना बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए मोदी आगे बढ़ रहे थे।

अब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो देखना होगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है? बांग्लादेश अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। बीते 15 सालों से बांग्लादेश भारत का सबसे करीबी सहयोगी रहा है। भारत के लिए सुरक्षित पूर्वोत्तर की धुरी ढाका में है क्योंकि म्यांमार में शक्ति का केंद्र कहां है, कोई नहीं जानता। इस बीच पाकिस्तान में नाटकीय बदलाव आए हैं। वहां नया सत्ता प्रतिष्ठान है और 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों के बाद भारत के साथ उसके संबंध लगभग समाप्त हो चुके हैं।

नेपाल में अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि उसने अपने राष्ट्रीय मानचित्र में बदलाव करके सामरिक महत्त्व के उस भारतीय भूभाग को अपना हिस्सा दिखा दिया, जहां से कैलास-मानसरोवर तीर्थ यात्रा का मार्ग गुजरता है। नेपाल की संसद में इस मानचित्र को सर्वसम्मति से मंजूरी भी मिल गई।

श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद एक अलग किस्म की क्रांति हुई। हंबनटोटा जैसे उसके प्रमुख बंदरगाह का चीन ने अधिग्रहण कर लिया। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू के उभार के पीछे 'भारत भगाओ' का नारा रहा और यह हाल ही की बात है। भूटान पर सीमा विवाद 'हल' करने का चीनी दबाव लगातार बना हुआ है और उससे कहा जा रहा है कि इसमें 'भारत के हितों की परवाह नहीं की जाए'।

क्या यह नाटकीय और बदतर दौर पूरी तरह भारत की गलतियों का नतीजा है? या भारत पीड़ित है? मगर इतने रसूख वाला भारत पीड़ित होने का दावा कैसे कर सकता है? आज हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शेष उपमहाद्वीप के कुल जीडीपी का चार गुना है। हमारी आबादी उनकी तीन गुना और वैश्विक शक्ति कई गुना है। भारत की जनता ने अपने गणतंत्र को पड़ोसी मुल्कों की तुलना में विशिष्ट बनाया है- एक संवैधानिक लोकतंत्र बनाया है, जहां सब कुछ लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और विश्वसनीय तरीके से होता है। इसलिए पीड़ित होने की बात छोड़ ही दीजिए।

दुनिया में सबसे अस्थिर पड़ोस हमारा ही है। ज्यादातर पड़ोसियों की आबादी बहुत अधिक है और शहरों में भीड़भाड़ है। उनकी आबादी में युवा ज्यादा हैं और अफ्रीकी देशों के उलट ज्यादातर ने लोकतंत्र को अपनाया है। बड़ी युवा आबादी और लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता की राय मायने रखती है।

शेख हसीना और उनके मित्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश में इसी बात की अनदेखी की। ये ऐसे देश नहीं हैं जहां कोई बेहद ताकतवर तानाशाह जनता की राय के खिलाफ जा सकता है। उनमें से हर एक देश का लोकतंत्र हमारी तुलना में अपूर्ण है लेकिन उनमें से किसी में पूरी तरह तानाशाही भी नहीं है। इन सभी देशों में आपको शासन और जनता के विचारों दोनों का ध्यान रखना होता है।

जनमत के लिए संप्रभुता भी मायने रखती है। अगर भारत दबाव बनाता नजर आएगा तो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हम नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में ऐसा होते देख चुके हैं। 2015 की नाकेबंदी ने गहरा जख्म दिया है। विदेश मंत्रालय यह जानता है और अक्सर सही बात कहता है। परंतु हमारा मीडिया खासकर सरकार के मित्रवत कहलाने वाले हिंदी समाचार चैनलों पर आने वाली खबरों पर गहरी नजर रखी जाती है। चरम राष्ट्रवादी सोशल मीडिया हैंडल उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं।

कुछ हैंडल तो बांग्लादेश में सेना भेजने, वहां रहने वाले 1.4 करोड़ हिंदुओं के लिए सीमाएं खोल देने और रंगपुर में उनके लिए बस्ती बनाने की सलाह तक दे रहे हैं।

मालदीव के साथ बिगड़ रहे संबंध सुधारने के लिए वहां गए विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस दिन लौटे उसी दिन अफवाह फैल गई कि मालदीव ने 28 द्वीप भारत को सौंप दिए। कुछ हिंदी चैनलों के प्राइम टाइम में इस पर बहस तक हो गई। किसी ने कह डाला कि 'मुइज्जु ने घुटने टेक दिए।' हमारे लिए यह मजाक हो सकता है, मालदीव के लोगों के लिए नहीं। करीब 50 लाख की आबादी और सात अरब डॉलर जीडीपी वाला वह देश भी हमारी तरह संप्रभु है।

आखिर में विदेश मंत्रालय ने सभी ट्वीट डिलीट कराए मगर तब तक देर हो चुकी थी। खुद को उस पड़ोसी की जगह रखकर देखिए। वे यही सुनते समझते होंगे कि भारत बहुत दबंगई से काम करता है। दबंगई अच्छी है लेकिन मानसिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक गुणों का क्या? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था विनम्रता के साथ क्षेत्र में शिक्षक बनना होगा। क्या हमारे शिक्षा संस्थान इतने अच्छे हैं कि वे पड़ोसी देशों के उन हजारों विद्यार्थियों को लुभा सकें, जो शिक्षा के लिए विदेशों में जाते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे आएं?

चरम राष्ट्रवादी मीडिया द्वारा अपमान की जगह छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, सांस्कृतिक प्रदर्शन और फिल्में हों तो कैसा हो? इकलौती महाशक्तियों का इतिहास बताता है कि सॉफ्ट पावर असल में हार्ड पावर या असली ताकत की सहायक नहीं है बल्कि उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या भारत में ऐसे थिंक टैंक हैं जो पड़ोसी देशों के विद्वानों को जगह दें, उन्हें सम्मेलनों के लिए बुलाएं, खुद की ट्रैक-2 प्रक्रिया चलाएं? ऐसा नहीं है कि भारत को यह सब पता नहीं है। इसीलिए हम नेपाल और भूटान से तो बिजली खरीदते हैं लेकिन बांग्लादेश को बिजली निर्यात करते हैं।

दूसरा पहलू है हिंदू कार्ड का जरूरत से अधिक प्रयोग। प्रधानमंत्री की नेपाल और बांग्लादेश यात्राओं के दौरान मंदिर भ्रमण को खास तौर पर प्रचारित किया गया। मगर हकीकत यह है कि हमारी सबसे लंबी सीमाएं मुस्लिम बहुल देशों के साथ मिलती हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो वे हमारी ओर सवालिया ढंग से देखते हैं। यह गजब ही है कि जब बांग्लादेश उबल रहा है और हमारी कूटनीति हालात संभालने में लगी है ठीक उसी समय एक बांग्लादेशी हिंदू को असम में सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई।

पांच वर्ष से और खासकर यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से भारत बहुध्रुवीयता, सामरिक स्वायत्तता और बहु-संबद्धता की बात करता रहा है। मगर हमारे पड़ोसी भी इस पर चल सकते हैं। अगर हम चीन के खिलाफ अमेरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन सभी के पास हमारे विरुद्ध चीन है।

ताकतवर अमेरिका भी अपने पड़ोसी देश क्यूबा को नहीं झुका सका। वेनेजुएला को भी नहीं। पड़ोसियों के साथ हमारी नीति वही होनी चाहिए जो वाजपेयी ने बनाई, मनमोहन सिंह ने अपनाई और जिसे मोदी ने ऊर्जा प्रदान की। हमें बस घरेलू राजनीति और अंध धार्मिकता से बचना होगा। साथ ही पड़ोसियों के प्रति अधिक नरमी दिखानी होगी और सम्मान बरतना होगा।

आज का इतिहास

1878 अमेरिकन बार एसोसिएशन सरसोटा में आयोजित किया गया।
1911 लियोनार्डो दा विंची की मोना लिसा को लुमब्रे से एमुजियम कर्मचारी द्वारा चुरा लिया गया था और दो साल बाद तक बरामद नहीं किया गया था।
1915 प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने तुर्की के विरूद्ध युद्ध की घोषणा की।
1918 सोमे की दूसरी लड़ाई शुरू होती है।
1938 इटली में सार्वजनिक और हाई स्कूलों में यहूदी शिक्षकों के पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया।
1938 राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सार्वजनिक रूप से कनाडा की रक्षा करने का वादा किया, एक दुश्मन को उस पर आक्रमण करना चाहिए, और बदले में उन्होंने कनाडा को अमेरिकियों की मदद करने का अनुमान लगाया, अगर वे हमले में थे।
1944 संयुक्त राष्ट्र के गठन पर चर्चा के लिए रिपब्लिक ऑफ चाइना, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन, डीसी में डम्बर्टन ओक्स से मुलाकात की।
1945 अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैरी के। डागलियन, जूनियर ने एक डेल्टा चरण प्लूटोनियम बम कोर पर गलती से टंगस्टन कार्बाइड ईंट गिरा दिया और 25 दिनों के बाद एक महत्वपूर्ण दुर्घटना के कारण घातक ज्ञात घातक न्यूट्रॉन विकिरण की घातक खुराक के लिए खुद को तैयार कर लिया।
1957 सोवियत संघ ने दुनिया की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आर-7 सेमेयोर्का का परीक्षण किया।
1957 अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी ईसेनहोवर ने परमाणु परीक्षण के लिए 2 साल के निलंबन की घोषणा की।
1965 रोमानिया में संविधान लागू हुआ।
1969 डोनाल्ड और डोरिस फिशर सैन ने फ्रांसिस्को के महासागर एवेन्यू पर पहला गैप स्टोर खोला।
1969 एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने अल-अक्सा मस्जिद को आग लगा दी, इस्लामिक सहयोग संगठन के गठन का एक प्रमुख कारण।
1982 स्विटजर लैंड के राजा सोभूजा द्वितीय का निधन हुआ।
1986 कैमरुन में ज्वालामुखी विस्फोट से निकली जहरीली गैसों से 2000 की मौत हुई।
1986 दुनिया के सबसे तेज तर्रार धावक यूसैन बोल्ट का जमैका में जन्म हुआ।
1986 पश्चिम अफ्रीका के कैमरून में ज्वालामुखी झील न्योस से घातक गैस ने 15 मील के दायरे में हर जीवित चीज़ को नष्ट कर दिया, जिसमें 1,500 लोग शामिल थे। गैस इसलिए हानिकारक थी क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर थे।
1986 न्योसिन कैमरून झील से कार्बन डाइऑक्साइड के एक बादल के एक घातक विस्फोट ने 1,700 लोगों और 3,500 पशुधन को मार डाला।

अब पहले जैसी नहीं होगी जम्मू-कश्मीर विधानसभा

कृष्णमोहन झा

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव तो पांच साल बाद ही हो रहे हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों को दस साल बाद अपने राज्य की विधानसभा चुनने का अवसर मिल रहा है।जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावीकरण के बाद पहली बार वहां होने वाले इन विधानसभा चुनावों पर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि इस अनुच्छेद को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पेश किया था जिसके माध्यम से सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था । जाहिर सी बात है कि आसन्न चुनावों के बाद गठित होने वाली विधानसभा का स्वरूप दस वर्ष पूर्व निर्वाचित विधान सभा से काफी अलग होगा। यह भी यहां विशेष उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब पांच वर्षों का होगा जबकि इसके 2014 के चुनावों तक यह 6 वर्षों का हुआ करता था। चूंकि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इसलिए वहां वहां राज्यपाल की जगह अब उपराज्यपाल होंगे । वर्तमान में मनोज सिंहा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं।2014 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटों के लिए मतदान हुआ था जिनमें जम्मू की 37, कश्मीर घाटी की 46 और लद्दाख की 4 सीटें शामिल थीं।परिसीमन के बाद हो रहे जम्मू-कश्मीर विधानसभा के इन चुनावों में अब 90 सीटों के लिए तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा। इनमें जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 सीटें शामिल हैं। लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहली बार उपराज्यपाल दो कश्मीरी प्रवासियों और एक पीओके से विस्थापित किसी व्यक्ति का मनोनयन करेंगे। कश्मीरी प्रवासी उसे 1 नवंबर 1989 के बाद राज्य के किसी भी हिस्से से पलायन करने वाले व्यक्ति को कश्मीरी प्रवासी माना जाएगा बशर्ते कि उसका नाम रिलीफ रजिस्टर में दर्ज हो। 90 सदस्यों वाली जम्मू-कश्मीर की न ई विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी। पिछली विधानसभा की भांति जम्मू-कश्मीर

की नयी विधानसभा में भी 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं जहां चुनाव नहीं कराए जा सकते।

परिसीमन के बाद जिस जम्मू-कश्मीर विधानसभा का स्वरूप बदल गया है उसी तरह जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं। 2014 में भाजपा ने जिस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उसकी मुखिया मेहमूदा मुफ्ती अब भाजपा की कट्टर विरोधी बन चुकी हैं। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)की संयुक्त सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया था । जनवरी 2016 में उनका निधन हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर चार महीने तक राष्ट्रपति शासन के आधीन रहा । तत्पश्चात मेहबूबा मुफ्ती ने भाजपा और पीडीपी की संयुक्त सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ ली परंतु जून 2018 में भाजपा ने मेहबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और तब से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 30 सितंबर तक राज्य विधानसभा के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब काफी हद तक हाशिए पर जा चुकी है। राज्य में उसे अपना जनाधार सिमटने का अहसास भी हो चुका है। यही स्थिति नेशनल कांफ्रेंस की है हालांकि हाल के लोकसभा चुनावों में वह राज्य की 6 लोकसभा सीटों में से 2 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी जबकि दो सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। भाजपा ने जिन दो सीटों पर जीत हासिल की उन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने कश्मीर की दो सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के इन चुनावों में भाजपा अगर शानदार जीत हासिल करने में सफल होती है तो उसकी जीत राज्य में संविधान के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावीकरण के उस फैसले पर भी मुहर होगी जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष में बिखराव की स्थिति का लाभ भाजपा को मिलना तय है। राज्य में कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी अस्तित्व में आ चुकी हैं जो भाजपा का समर्थन कर सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसके कुछ नेता फिर से कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। कुल मिलाकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के इन चुनावों में अभी तक भाजपा, नेशनल कांफ्रेंस , कांग्रेस और पीडीपी की सक्रियता दिखाई दे रही है। अगले कुछ दिनों में नये राजनीतिक समीकरण बन गए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी लेकिन अभी भाजपा सबसे आगे दिखाई दे रही है जिसने अकेले अपने दम पर चुनाव लडने की घोषणा कर दी है।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की वास्तविक चुनौतियां

राजकुमार सिंह

मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार ने हिंसाग्रस्त बांग्लादेश की सत्ता संभाल ली है। 84 साल के यूनुस राजनेता नहीं, माइक्रो फाइनेंस की सोच के साथ ग्रामीण बैंक स्थापित कर करोड़ों गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं। देश के संकटकाल में उन पर विश्वास के लिए शायद यही उनकी सबसे बड़ी योग्यता बन गई। हसीना सरकार ने जिन यूनुस को जनता का दुश्मन कहा था, उन्हें लोग गरीबों का बैंकर कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी सत्ता और जनता की सोच-समझ में यह अंतर चिंतन का विषय होना चाहिए, लेकिन यूनुस की असली परीक्षा अब होगी। हसीना के शासनकाल में दर्ज एक मामले में जमानत पर चल रहे और अंतरिम सरकार की बागडोर

संभालने के लिए ही फ्रांस से बांग्लादेश लौटे यूनुस ने हालिया आंदोलन और तख्तापलट को देश की 'दूसरी आजादी' करार दिया है। पाकिस्तान के दमनचक्र से मुक्ति दिलवा कर पूर्वी पाकिस्तान को पृथक देश बनवाने वाले बंग-बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी शेख हसीना का तख्ता पलट कर उनकी पार्टी अवामी लीग तथा मुक्ति संग्राम में कंधे-से-कंधा मिला कर लड़े अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसाग्रस्त बांग्लादेश को यह दूसरी आजादी आखिर किससे मिली है? अगर यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण और शेख हसीना सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध था तो फिर तख्ता पलट के बाद शेख मुजीब की प्रतिमाओं सहित अवामी लीग के नेताओं तथा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जाहिर है, धार्मिक कट्टरता के जरिये बांग्लादेश को पुन- उसी अंधेरी सुरंग में धकेलने की साजिश की जा रही है, जिससे वह लंबे संघर्ष के बाद 1971 में भारत की मदद से निकल पाया था। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तथा कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी की पाकिस्तानपरस्ती जगजाहिर है। पाकिस्तान और चीन का भारत विरोधी गठजोड़ भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि छात्र आंदोलन को सत्ता विरोधी आंदोलन में बदलने में परदे के पीछे किसकी भूमिका रही। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू विरोधी हिंसा में भी उन्हीं ताकतों की भूमिका न मानने का कोई ठोस कारण नहीं है। यह अच्छी बात है कि आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने ऐसी हिंसा से बचने की अपील की है। यूनुस भी इसे गलत मानते हैं, लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। शाब्दिक उपदेशों से आगे बढ़ कर ऐसी हिंसा पर सख्ती से अंकुश लगाना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस की आर्थिक समझ पर संदेह का सवाल ही नहीं, पर राजनीति, खासकर सत्ता-राजनीति के षड्यंत्रकारी चरित्र को समझना सज्जनों के लिए अक्सर मुश्किल होता है।

ग्रामीण भारत को सशक्त करें

रामबहादुर राय

स्तंवत्रता की जो परिकल्पना स्वाधीनता सेनानियों की थी, उसमें स्वतंत्रता प्रति के बाद भारी भटकाव हुआ, ऐसा मुझे लगता है। उस परिकल्पना के मूल में यह बात थी कि भारत जब स्वतंत्र होगा, तो वह अपनी व्यवस्थाएं लागू करेगा, जैसा समाज हमारा पहले था, उसकी नींव पर देश अपना पुनर्निर्माण, नवनिर्माण करेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो प्रधानमंत्री आये, उनके इरादे नेक थे, लेकिन ज्यादातर प्रधानमंत्री भटके हुए थे। यह भटकाव दरअसल समझ का है। मेरे ऐसा कहने का अर्थ यह है कि चाहे वह 1905 से 1908 तक का दौर हो या 1920 से 1947 तक का दौर हो, यही वे दो दौर हैं, जब भारत की स्वतंत्रता की परिकल्पना की गयी थी।

वर्ष 1905 में नौ अगस्त को चार व्यक्ति- बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो और रवींद्रनाथ ठाकुर- कोलकाता में एकत्र हुए थे। उन्होंने स्वदेशी का प्रारंभ किया। साल 1920 में जब गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, तो उन्होंने जो विधान कांग्रेस के लिए बनाया, उसमें खादी था, चरखा था, यानी स्वदेशी आयाम था। उसका बड़ा असर ब्रिटेन की कंपनियों पर पड़ा। परंतु आजादी के बाद हमने जो रास्ता चुना, उसमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को ही चलाये रखा और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। हालांकि पहले और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अच्छा काम किया था और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उनको अगर सरकारों ने स्वीकार कर उन पर अमल किया होता, तो भी कुछ सार्थक परिवर्तन हो सकता था।

चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो या चुनाव का बड़ा भारी खर्च हो, अमीरी और गरीबी की चौड़ी खाई हो, क्षेत्रीय विषमता हो, दलित एवं आदिवासी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, यह मसला हो, सीमा की सुरक्षा का विषय हो, ऐसी तमाम समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा मेरा मानना है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, मनुष्य की बड़ी शक्ति है, प्रतिभा है, यह सब होने पर भी इन सबका लाभ बाहर के लोगों को मिल रहा है। हमें स्वतंत्रता मिली थी देशभक्ति और बलिदान के बल पर। इसका ठीक उल्टा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी है कि 2023 तक लगभग ढाई लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने

नागरिकता छोड़ी है, उन्हें भगाया नहीं गया है, उनका दमन नहीं हुआ है, वे बड़े संपन्न लोग हैं। वे भारत को छोड़ कर ऐसे 'टैक्स हेवन' देशों में गये हैं, जहां वे अपनी कमाई और कई गुना बढ़ा सकते हैं।

स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प उत्साहजनक है, श्रेष्ठ है। पर यहां प्रश्न यह है कि क्या हम उस लक्ष्य की ओर पूरे तन-मन से आगे बढ़ रहे हैं। शासन जिनको चलाना है, यानी शासन तंत्र, यहां मैं राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, का स्वभाव, रंग-ढंग, आम लोगों के प्रति उसका रवैया सही नहीं है। जब तक शासन तंत्र को पूरी तरह जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक हम लक्ष्य चाहे जो रखें, उस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी कठिनाइयां आयेंगी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधी का रास्ता छोड़ दिया, जिसके कारण कई तरह की विपदा भारत पर आयी है और आगे भी आती रहेगी। यह समस्या के मूल में है। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज की व्यवस्था स्थापित हो। इस संबंध में मैंने जितना भी पढ़ा-लिखा है, उसके आधार पर मेरा यह स्पष्ट मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए एक ऊंचा लक्ष्य रखा है, वह प्रेरक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि यह हासिल कैसे होगा। इसके लिए मुझे एक ही मंत्र का पता है। यह लक्ष्य तब हासिल होगा, जब भारत में गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, गांव खुशहाल बनेंगे, गांव के हाथ में सत्ता आयेगी और वे अपना निर्णय स्वयं कर सकेंगे।

इस दिशा में देर से सही, पर एक अच्छा कदम नब्बे के दशक के शुरू में भारत सरकार ने उठाया। वह कदम था संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करना। इससे पंचायती राज कायम करने में जो कमी रह गयी थी, वह दूर हुई। आज जो जरूरत है, वह यह है कि 73वें संविधान संशोधन का एक ठोस मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या उससे वास्तव में गांवों को ताकत मिली है। अगर गांवों का समुचित सशक्तीकरण नहीं हो सका है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि कानून में क्या बदलाव किये जाने की जरूरत है। यह भी ध्यान देने की बात है कि यह विषय राज्यों का है। विभिन्न राज्यों में अपनी सुविधा और समझ से कानून बनाये गये हैं। राजनीतिक नेतृत्व को हम संचालन करते हुए देखते हैं, पर वास्तव में संचालन की भूमिका प्रशासन तंत्र द्वारा निभायी जाती है। प्रशासन तंत्र पंचायती राज व्यवस्था को आज भी लागू नहीं करना चाहता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत अच्छे से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है। लेकिन यह कहने का मतलब यह नहीं है कि उसने सब कुछ कर ही दिया है। कई राज्यों में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन किसी भी राज्य में ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिला है।

मेरा कहना है कि ग्राम सभा को अधिकार मिले, बजट मिले, कर्मचारी मिलें। उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार मिले। जो जिलाधिकारी होता है, अगर वह जिला पंचायत के अधीन होगा, तो स्थिति बेहतर होगी। दूसरी बात सांसद निधि के संबंध में है, जो इससे जुड़ी हुई है। नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत की सरकार थी, तब इस सांसद निधि योजना को लाया गया था, जो वास्तव में सांसदों को एक प्रकार की रिश्वत थी। उस निधि के कारण हमारे जन-प्रतिनिधियों का चरित्र बदल गया है। लोगों की निगाह में वे संदेहास्पद हो गये हैं क्योंकि वे जिला प्रशासन और ठेकेदारों के साथ मिलकर उस धन को खर्च करते हैं। सभी लोग बहुत भ्रष्ट हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर लोगों की निगाह में सांसद निधि के कारण जन-प्रतिनिधियों की छवि खराब हुई है, जबकि एक दौर था, जब लोग उन्हें बड़े सम्मान से देखा करते थे। यह सांसद निधि पंचायतों में खर्च होती है, तो क्यों नहीं इस योजना को बंद कर यही धन सीधे ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए। यदि इतनी-सी बात पर ध्यान दिया जाए, तो उत्साहजनक वातावरण बनेगा। यह देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

भारत से 71 में ही हो गई थी बड़ी चूक

शिवदान सिंह

बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आईं शेख हसीना ने पूरे घटनाक्रम पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण वह बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दे। लेकिन विचारणीय पहलू यह है कि भारत ने सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान से युद्ध किया और 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त करके बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की।

भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों और उनके कमांडर जनरल नियाजी को बंदी बना लिया था। इस युद्ध में 3,000 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 12,000 घायल हुए। इसके अलावा इस युद्ध में भारत की एक पंचवर्षीय योजना पर होने वाले धन के बराबर धन खर्च हुआ, जबकि उस समय देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। यह धन देश की विकास योजनाओं पर खर्च किया जाना था। परंतु मानवता की पुकार के कारण भारत सरकार ने यह धन बांग्लादेश के निर्माण पर खर्च किया। युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्वस्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बगैर ही बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और युद्ध समाप्ति के 15 दिन बाद ही अपनी सेना को बांग्लादेश से वापस बुला लिया। यहां पर विचारणीय यह कि लंबे समय से पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित है, हिंदू अल्पसंख्यकों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे थे, जिसके कारण या तो वे पलायन कर रहे थे या फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो रहे थे। आजादी से पहले 1946 में बांग्लादेश स्थित नोहा खाली नाम के स्थान पर हुए सांप्रदायिक दंगे में कई हिंदुओं की हत्याएं की गईं और महिलाओं से दुष्कर्म किए गए। महात्मा गांधी भी इन दंगों को नहीं रोक पाए

थे।

1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 18 फीसदी और पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में 25 फीसदी थी, लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी घटकर एक प्रतिशत और बांग्लादेश में केवल पांच फीसदी रह गई है। दोनों ही देशों से अब भी हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं। इतना सब होने के बाद भी बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने और उसका निर्माण करने में अपने 3,000 सैनिकों की कुर्बानी और अपनी एक पंचवर्षीय योजना का पूरा धन खर्च करने के बाद भी भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाई। न्याय और मानवता के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में उसके निर्माण के समय ऐसे प्रावधान किए जा सकते थे, जिससे वहां की कानून व्यवस्था हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उस समय बांग्लादेश की सरकार भारत की हर शर्त मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि भारत ने ही उसे पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जहां पर किसी देश ने दूसरे देश को बांग्लादेश की तरह स्वतंत्रता?दिलाई हो।

भारत ने जिस देश को लंबी गुलामी से मुक्त कराया, उसके साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके अनुसार, उसके कानून में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान हो। इसके अलावा भारत की ओर से किए गए अनके आर्थिक अनुबंधों की वजह से बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की एक उभरती आर्थिक शक्ति बन रहा है। सीमाओं पर भी भारत ने उसे सुरक्षा प्रदान की है। पूरी बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही है। परंतु आज उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिससे मानवता शर्मसार हो रही है।

इस समय भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में जो भी सरकार आती है, उसे साफ शब्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करने के लिए कहे, अन्यथा भारत अपने आर्थिक संबंध बांग्लादेश से समाप्त कर देगा। उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाकर उसको भी पाकिस्तान की तरह एक आतंकी देश घोषित करवा सकता है। इस्राइल एक छोट-सा देश है, लेकिन पूरे विश्व के यहूदियों को वह संरक्षण उपलब्ध करा रहा है। क्या भारत भी इस प्रकार हिंदुओं की रक्षा कर सकता है? परंतु हमारे देश में धर्म निरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं की बात ही नहीं की जाती। अल्पसंख्यकों को वोट बैंक माना जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की घटनाओं को देखते हुए अब समय आ गया है कि भारत सरकार विश्व पटल पर खुलकर हिंदुओं की रक्षा की बात रखे।

जरूरी है सर्वाधिक वंचितों का विकास

प्रो बद्री

तंत्र भारत में बीते साढ़े सात दशकों में वंचित समुदायों की सामाजिक गतिशीलता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। उनमें राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी है तथा लोकतांत्रिक और सामाजिक क्षमता का वितरण हुआ है। लेकिन यह वितरण समुचित और अपेक्षित नहीं है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में उप-वर्गीकरण की बात कही है। इस पर बहस चल रही है। इस व्यवस्था में उन्हीं लोगों को अधिक लाभ होगा, जिनमें प्रतिस्पर्धा की क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी। उन्हीं लोगों में आकांक्षा और आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता भी अधिक होगी। इसे प्रतिनिधित्व की राजनीति कहा जाता है। अभी तक वंचित समुदायों में उन जातियों और जनजातियों को अधिक लाभ पहुंचा है, जिनकी संख्या अधिक है, जिनमें बुद्धिजीवी अधिक हैं। इसके ऐतिहासिक कारण हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी ऐसी जातियों का योगदान रहा है। यह स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग में भी है। उसी समय से अनेक जातियों में नेताओं के उभरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे नयी व्यवस्थाएं आयीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, उन्होंने उसका अधिक लाभ उठाया क्योंकि उनमें शक्ति थी। दूसरी तरफ कई समुदायों में आकांक्षा की क्षमता अपेक्षित गति से नहीं पनप सकी या नहीं पनपी। इस वजह से वे समुदाय पीछे रह गये हैं। उन्हें आगे कैसे लाया जाए और आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचाया जाए, यह आज एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान का एक रास्ता तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर सहमति बने या उस पर गंभीरता से विचार किया जाए। लेकिन राजनीतिक वर्ग के अपने समीकरण होते हैं। वे वोट बैंक के हिसाब से चलते हैं। अगर नैतिक राजनीतिक वर्ग होगा, तो वह वंचितों में सबसे वंचित के बारे में भी सोचेगा। जैसे गांधी जी भी अंतिम व्यक्ति की बात करते थे। सामाजिक पंक्ति में एक के बाद एक व्यक्ति खड़ा है, उसके बाद भी कोई है। तो, नैतिक मानसिकता तो यही होनी चाहिए कि सबसे वंचित का भी ध्यान रखा जाए। निश्चित रूप से बीते साढ़े सात दशकों में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी और लोकतांत्रिक पैठ गहरे तक हुई है, पर इसमें निरंतरता होनी चाहिए और यह प्रवाह नीचे से नीचे तक जाना चाहिए। यह केवल आरक्षण या राजनीतिक प्रतिनिधित्व से नहीं होगा। इसके लिए उन समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण भी आवश्यक है। समय-समय पर जो कल्याण कार्यक्रम या नीतिगत पहलें होती रहती हैं, जैसे अन्न योजना, पोषण योजना, वित्त उपलब्धता आदि, उनसे भी वंचितों की गतिशीलता को बड़ी मदद मिलती है। अगर कोई वंचित कुछ सक्षम होगा, तभी वह आरक्षण का फायदा उठा सकेगा। धीरे-धीरे उसके भोजन की समस्या दूर होती है, कुछ बचत कर पाता है, फिर अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, जो रोजगार के लिए फिर स्पर्धा कर पाता है। आगे के विकास के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे राजनीतिक वर्गों का उभार हो, जो अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचे। लेकिन हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक क्षेत्र से आयीं। आरक्षित वर्गों में जो वर्चस्वशाली जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत उप-वर्गीकरण के सुझाव को खारिज कर दिया। जो वर्ग बहुत अधिक वंचना से ग्रस्त हैं, उनके पास ऐसा नेतृत्व नहीं है और न ही बड़ी संख्या है कि वे अपनी आवाज प्रभावी ढंग से उठा सकें। आप टीवी की बहसें देख लें, अखबारों की टिप्पणियां देख लें, उनकी ओर से बोलने वाला ही कोई नहीं है। सामाजिक गतिशीलता की दृष्टि से देखें, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की स्थिति में कुछ अंतर दिखाई देता है। इसी तरह महानगरों और गांवों-कस्बों का फर्क भी है। दक्षिण भारत में बहुत सी वंचित जातियां आगे बढ़ने की आकांक्षा रखने लगी हैं। उनमें राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी है। इसलिए वे अपने हितों और अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी हैं। जैसा मैंने पहले कहा, उत्तर भारत में कई समुदाय हैं, जिनके पास राजनीतिक नेतृत्व और बौद्धिक लोग नहीं हैं। इसलिए हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। रही बात गांव और शहर की, तो जो लोग शहरों का रुख कर लेते हैं, उन्हें पढ़ाई-लिखाई से लेकर कमाई के अधिक अवसर मिलने लगते हैं, जो गांवों या कस्बों में उपलब्ध नहीं होते।

शादीशुदा जिंदगी में इन बातों को करें फॉलो

लड़ाई-झगड़ा, प्यार-मोहब्बत, हर रिश्ते में होना लाजमी है। लेकिन अगर ये झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगे तो ये अच्छा नहीं होता क्योंकि इससे रिश्ते टूट सकते हैं। किसी भी रिश्ते में लड़ाई होना बेहद खराब है, हां हल्की-फुल्की नोक झोंक तो हर घर में होती है, पर जब ये ज्यादा होने लगे तो खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। आइए, जानते हैं-

विश करें

तो क्या हुआ कि आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं, प्यार को बरकरार रखने के लिए आपको हर चीज करनी चाहिए। भले ही आप दोनों के उठने का समय अलग है लेकिन आप दोनों को सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। साथ ही रात में सोने पर भी आपको गुड नाइट विश करके सोना चाहिए। ये एक अच्छी आदत होने के साथ-साथ आपके रिश्ते को जीवित रखने में मदद करता है।

फूल

फूल किसे पसंद नहीं होते, इन दिनों फेस्टिव सीजन है तो यकीनन आपकी वाइफ भी रोजाना अच्छे से तैयार होती होंगी। ऐसे में उनको आप फूल दे सकते हैं। वह इसे अपने बालों में लगा सकती है और ये सच में काफी रोमांटिक होगा।

तारीफ

एक दूसरे की तारीफ करें। आप अपने पार्टनर की किसी फोटो या फिर वो दिन भर कैसी लग रही थी इस बात की तारिफ करें। रोजाना आप दोनों मेहनत करते हैं तो ऐसे में एक दूसरे के काम की तारीफ भी कर सकते हैं।

हाई हील पहनने की हैं शौकीन, पूरे दिन पहनकर रखने के लिए अजमाएं ये हैक्स

हील्स पहनना अधिकतर महिलाओं को पसंद होता है। हील्स पहनने के लिए किसी भी परफेक्ट आउटफिट पहनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि किसी भी लुक को परफेक्ट बनाने के लिए आप हील्स पहन सकते हैं। हील्स की एक खासियत यह भी है कि यह पैरों को ज्यादा लंबा दिखाते हैं, जिससे आपका लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हाई हील्स के साथ एक समस्या यह होती है कि यह बहुत ज्यादा देर तक आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं करवाते हैं। इसलिए अगर आप ऑफिस में या फिर किसी मैरिज फंक्शन आदि में पहन रही हैं तो हो सकता है कि आपको पैरों में दर्द का एहसास होने लगे। तो जानते हैं हाई हील्स से जुड़े कुछ हैक्स के बारे में।

हैक 1

डबल टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप तलवे से चिपका दें। यह ट्रिक आपके फुटवियर को पैरों पर ज्यादा आरामदायक तरीके से रखेगी। साथ ही इसके कारण होने वाले फफोले और पैर की उंगलियों में दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा।

हैक 2

हील्स में आप इनसोल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सिलिकॉन या कपड़े से बने होते हैं। यह आपके पैरों को हाई हील्स में आगे बढ़ने से रोकते हैं, साथ ही आरामदायक भी होते हैं।

हैक 3

पार्टी में अक्सर हील्स उतारने का मन करता है, लेकिन आप ऐसा करने से बचें क्योंकि जब आप हील्स उतारते हैं तो उस पल तो आपको राहत मिल जाती है लेकिन कई बार ऐसा करते ही पैरों में सूजन आ जाती है और फिर जब आप हील्स दोबारा पहनती हैं तो पैरों में ज्यादा दर्द होता है।

हर लड़की को सीखनी चाहिए ये चीजें

यूं तो आज लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। घर की जिम्मेदारियों से लेकर बाहर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने तक में, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए एक खास जगह बनाई है। बावजूद इसके आज जानते हैं वो 5 चीजें जिन्हें होम मेकर हो या कोई प्रोफेशनल लड़की, जरूर सीखना चाहिए।

अकाउंट्स मेनटेन रखना

घर संभालना हो या फिर बाहर रहकर नौकरी करते हुए अपने खर्चों को करना हो मैनेज, लड़कियों को अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेने आने चाहिए। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपना अकाउंट्स मेंटेन करना जरूर आना चाहिए। आप ऐसा करते हुए आप अपने खर्चों पर भी खुद नजर रख पाएंगी। इसके अलावा लड़कियों को समय पर टैक्स रिटर्न भरना भी जरूर सीखना चाहिए। अपने रिटायरमेंट प्लान से लेकर सेविंग्स तक की प्लानिंग के लिए अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें।

साइन करने से पहले हर कागज को अच्छे से पढ़ें

ज्यादातर लोग अक्सर किसी डॉक्यूमेंट या कागज को बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। आपकी ये आदत आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। लड़कियों का मन कोमल होता है। आपका किसी पर विश्वास करना उचित है बावजूद इसके आपको समझदारी से काम लेना भी आना चाहिए। ऐसे में कभी भी किसी भी लीगल या जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले उसे जरूर अच्छे से पढ़ें।

बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स

वक्त चाहे कोई भी क्यों न हो, आप अपनी किस्मत को आजमाने के लिए रात या दिन का इंतजार थोड़े ही करेंगे। रात हो या दिन, आपको अपनी सुरक्षा के लिए बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स जरूर आने चाहिए ताकि आप मौका पड़ने पर किसी भी जगह सुरक्षित रह सकें। आप इसके लिए वीकेंड पर सेल्फ डिफेंस कोर्स कर सकती हैं।

सिग्नेचर डिश

हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी खासियत की

घर की जिम्मेदारियों से लेकर बाहर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने तक में लड़कियों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए एक खास जगह बनाई है।

वजह से लोगों के बीच पहचाना जाता है ऐसे में आप भी अपनी किसी सिग्नेचर डिश की वजह से लोगों के बीच फेमस हो सकते हैं। जब आप डिनर या पार्टी के लिए लोगों या दोस्तों को अपने घर बुला रही हैं तो मेन्यू में आपकी एक सिग्नेचर डिश तो होनी ही चाहिए जिसका स्वाद वो सालों-साल याद रखें।

कार का टायर बदलना

अक्सर लोगों को लगता है कि गाड़ी का टायर बदलने का काम सिर्फ लड़के ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी ड्राइव करती हैं तो यह काम आपको भी जरूर सीखना चाहिए वरना आप कभी भी मुश्किल में पड़ सकती हैं।

डेटिंग प्रोफाइल के लिए फोटो चूज करने में इन टिप्स की लें मदद

ऑनलाइन डेटिंग करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जब आप ऑनलाइन प्रोफाइल को सेट करते हैं तो आप पूरी तरह से सभी कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसे देख आसानी से कोई भी इंप्रेस हो जाए। हालांकि आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके प्रोफाइल का बायो पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप ज्यादा से ज्यादा मैच पा सकते हैं। इन सभी के साथ ये भी जरूरी है कि आप एक सही प्रोफाइल फोटो चूज करें। ऐसे में आप जब भी डेटिंग प्रोफाइल फोटो चूज करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखें। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी प्रोफाइल फोटो सेट कर सकत हैं।

टिप 1

ऐसी फोटो चूज न करें जिसमें आपका चेहरा क्लीयर न हो, या फिर आपका चेहरा दिख ही न रहा हो। ये फोटो अच्छा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सामने वाले को आपकी फोटो ही नहीं दिखेगी। ऐसी फोटो चुने जिसमें आप पूरी तरह से दिख रहे हों।

टिप 2

कई बार लोग डेटिंग एप पर ग्रुप फोटो लगाते हैं, ऐसे में सामने वाले को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोफाइल किसकी है। तो ध्यान रखें की फोटो सिर्फ आपकी हो न की ग्रुप फोटो हो।

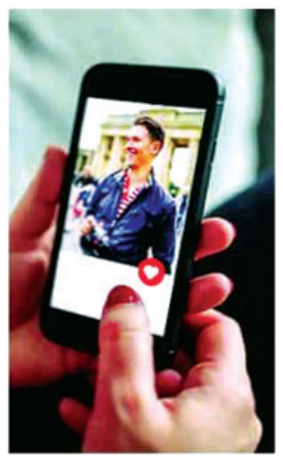

टिप 3

ऑनलाइन डेटिंग एप पर अगर आप फोटो स्लेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी फोटो लगाएं जो आपको डिस्क्राइब करे। अगर आपको कैंपिंग पसंद है तो आप कैंपिंग की फोटो लगा सकते हैं या फिर अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो किसी लाइब्रेरी की फोटो लगा सकते हैं।

टिप 4

एक ऐसी फोटो लगाएं जिसमें आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कई बार लोग अपने कपड़ों के साथ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं फिर भी उन कपड़ों में वह प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं।

कहीं आपकी चांदी की ज्वेलरी नकली तो नहीं है? ऐसे जानें

सोना और प्लेटिनम की तरह ही चांदी भी एक लोकप्रिय धातु है। आमतौर पर लोग सोने और चांदी के गहने पहनना पसंद करते हैं और वास्तव में चांदी के गहने दिखने में खूबसूरत भी लगते हैं। जब बात चांदी के गहनों को आती है तो लोग मुख्य रूप से इसकी पायल और बिछिया पहनते हैं। चांदी एक कीमती धातु है जो बहुतायत में पाई जाती है और इसका उपयोग गहनों के अलावा पूजा के सिक्के, सजावटी सामान, मूर्तियां और अन्य टिकाऊ वस्तुएं जैसे बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है।

यह एक नरम धातु है और यदि आप अपनी चांदी से बनी चीजों की उचित देखभाल करते हैं, तो यह लंबे समय तक नए जैसी बनी रहती हैं। चाहे आप चांदी के झुमके की एक जोड़ी खरीदें या स्टर्लिंग चांदी से बनी चांदी की अंगूठी और पायल, यदि आप इसकी अच्छी देखभाल करेंगी तो या सालों साल नयी जैसी बनी रहेंगी। लेकिन देखभाल के साथ आपके लिए इन्हें खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप जो चांदी खरीद रही हैं वो असली और शुद्ध है या नहीं। वास्तव में यदि आप नकली चांदी खरीदेंगी के बाद भी ये जल्दी ही खराब होने लगती है। आइए जानें कि आप किन युक्तियों से इस बात का पता आसानी से लगा सकती हैं कि आपकी चांदी असली है या नहीं।

लेबल की जांच करें

चांदी की वस्तु असली है या नकली यह जांचने के लिए आभूषण पर लेबल की जांच करना। यदि उस पर एक छोटा लेबिल है जिसमें स्टर' या 'स्टर्लिंग' प्रिंट है, तो इसका मतलब है कि वस्तु चांदी या चांदी चढ़ाया हुआ। जब भी चांदी की वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय या घरेलू स्तर पर बेचा जाता है, तो एक हॉलमार्क ट्रेड स्टैम्प होता है जो धातु को प्रमाणित करता है। किसी दुकान से चांदी की वस्तु खरीदने से पहले, हमेशा 'स्टर्लिंग' के मानक स्टैंप की जांच जरूर करें।

मैग्नेट टेस्ट

मैग्नेट का उपयोग करके यह जांचने का एक और अच्छा तरीका है कि आपने जो चांदी खरीदी है वह असली है या नकली। यदि आपके घर में कोई भी चुम्बक पड़ा हुआ है, तो आप इसका उपयोग प्रदर्शित करती है। इसके लिए एक मैग्नेट का प्रयोग करें और उसे चांदी की वस्तु के करीब लाएं जिसे आप जांचना चाहते हैं और देखें कि क्या यह मैग्नेट से मजबूती से चिपकती है। यदि ऐसा है तो समझ लें कि ये असली चांदी नहीं है (मोतियों की ज्वेलरी की ऐसे करें केयर)

आइस क्यूब टेस्ट

चांदी के शुद्ध होने या न होने की जांच करने का एक और आसान तरीका बर्फ के टुकड़े का उपयोग करना है। यह विधि चांदी के सिक्कों और अन्य चांदी की वस्तुओं के सपाट सतहों के परीक्षण के लिए आदर्श है। चांदी के सिक्के या गहनों पर आइस क्यूब रखें। यदि आइस क्यूब जल्दी पिघलती है, तो आपके पास जो चांदी की वस्तु है वह असली है। दरअसल चांदी में किसी सामान्य धातु की तुलना में अत्यधिक मात्रा में थर्मल कंडक्टिविटी होती है जो बर्फ को तुरंत पिघला देती है।

वजन परीक्षण

चांदी अधिकांश धातुओं की तुलना में ज्यादा हैवी होती है। इस धातु के वजन में एक विशिष्ट व्यास और मोटाई होती है। यदि चांदी का वजन कम होता है, तो यह स्टर्लिंग चांदी के बजाय हल्के चांदी के मिश्र धातुओं से बनी हो सकती है। यदि इसका वजन अधिक है, तो आमतौर पर चांदी की परत वाली वस्तुओं की तुलना में ठंडी होती है और चमकदार होती है।

ब्लीच टेस्ट

चांदी की धातु की प्रामाणिकता की जांच के लिए ब्लीच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस चांदी की वस्तु पर ब्लीच की एक बूंद डालें। ब्लीच जैसे ऑक्सीडाइजिंग केमिकल के संपर्क में आने के बाद अगर यह धूमिल हो जाए तो यह असली चांदी है। ब्लीच के संपर्क में आने पर असली चांदी तुरंत काली हो जाएगी जबकि नकली धातु पर ब्लीच का कोई असर नहीं होता है। लेकिन हिस्से में ही ब्लीच डालें।

इन सभी युक्तियों से आप अपनी चांदी के गहनों की जांच कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि चांदी असली है या नकली।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

आखिर राजनाथ सिंह के इतने मुरीद क्यों हुए एमके स्टालिन

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ

एम करुणानिधि पर स्मारक सिक्का जारी करने के एक दिन बाद, डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इससे उनकी पार्टी और भाजपा के बीच की खाई कम होने का संकेत मिलता है। एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी पर इस कार्यक्रम की आलोचना करने के लिए हमला करते हुए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि स्मारक सिक्के पर हिंदी में पाठ था, स्टालिन ने कहा कि यह केंद्र सरकार का एक समारोह था, जो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था, और ईपीएस की टिप्पणी उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। हालांकि, एमके स्टालिन इस कार्यक्रम के बाद केंद्र और खासकर के राजनाथ सिंह के मुरीद दिखे। स्टालिन ने राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने डीएमके के संरक्षक एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया है।

पीडीपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में आगामी तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जिन आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हैं। इल्तिजा मुफ्ती परिवार की पारंपरिक सीट बिजबेहरा से चुनाव लड़ेंगी। वह वरिष्ठ पार्टी नेता अब्दुल रहमान वीरी की जगह लेंगी, जिन्होंने 1999 से 2018 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और अब उन्हें अनंतनाग पूर्व से स्थानांतरित कर दिया गया है। महबूबा ने पहले घोषणा की थी कि वह अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पूर्ववर्ती राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए जाने और विधानसभा को अशक्त किए जाने का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगी।

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की बिगड़ी तबीयत

नईदिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी को तेज बुखार के बाद सोमवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। शाम को येचुरी को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया। येचुरी को पहले इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और फिर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उनरी पार्टी ने आज बताया कि सीताराम येचुरी को कल 19 अगस्त को सीने में संक्रमण के कारण एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। येचुरी, जो सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं, ने हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई थी। येचुरी को पूर्व महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत की गठबंधन निर्माण विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। येचुरी 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) में शामिल हुए और एक साल बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए।

एमवीए के साथ गठबंधन को तैयार ओवैसी की पार्टी

नईदिल्ली। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने

कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में विपक्ष के महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के साथ हाथ मिलाने को इच्छुक है। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन के लिए पार्टी को साथ लेकर चलना फायदेमंद होगा, अन्यथा पार्टी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही कहा था और हम एमवीए को फिर से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दे रहे हैं क्योंकि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। लेकिन यह उन पर निर्भर करता है कि वे हमें गठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा, राकांपा और शिवसेना के महायुति गठबंधन को हराने के लिए विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के साथ गठबंधन में चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है।

एक्स पर क्यों ट्रेंड हुआ 21 अगस्त को भारत बंद?

नईदिल्ली। एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को देशव्यापी विरोध (भारत बंद) का आह्वान किया है। राजस्थान में एससी/एसटी समूहों ने कहा कि उन्होंने बंद को समर्थन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस को सभी जिलों में तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है। पुलिस ने कहा कि भारत बंद के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एसपी को निर्देश दिए गए हैं। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति दी थी, और कहा था कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के विरोध में और कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार, एफआईआर में देरी पर भी उठाये सवाल

नईदिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को भयावह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगायी।

मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह घटना पूरे भारत में चिकित्सकों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थागत मुद्दे को उठाती है। इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेने वाली भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं।

शीर्ष न्यायालय ने बलात्कार-हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे ? पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, ''ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की।''

पीठ ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगायी और पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी। उसने पूछा कि जब आरजी कर अस्पताल के प्राचार्य का आचरण जांच के घेरे में है तो उन्हें

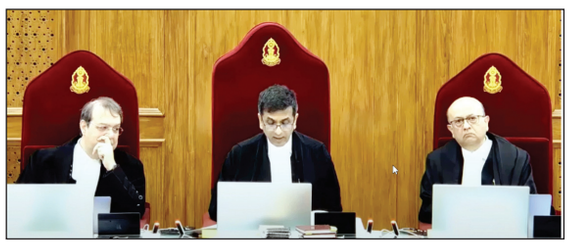

कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय संशुद्धि का वक्त है। न्यायालय ने कहा कि ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं और कार्य स्थल पर सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को चीजों को नकारने की स्थिति में न रहने दें और राज्य में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गयी है। उन्होंने कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना आर जी कर अस्पताल में नहीं घुस सकती। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेना इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही कार्रवाई की है और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है।

महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर चिकित्सकों की हड़ताल को रविवार को एक सप्ताह हो गया और अब यह दूसरे सप्ताह भी जारी है जिससे मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। प्रदर्शनरत चिकित्सक चाहते हैं कि सीबीआई दोषियों को पकड़े और अदालत उन्हें मौत की सजा दे। वे सरकार से इस बारे में आश्वासन भी चाहते हैं कि ''भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।''

उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शनरत चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि उनकी चिंता को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के एक सेमीनार हॉल में जूनियर चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए।

अस्पताल के चेस्ट विभाग में नौ अगस्त को सेमीनार हॉल के भीतर चिकित्सक का शव पाया गया था जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। कोलकाता पुलिस ने इस घटना के संबंध में अगले दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया और सीबीआई ने 14 अगस्त को जांच शुरू कर दी। उच्च न्यायालय ने मृतका के माता-पिता की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। मृतका के माता-पिता ने अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया था।

लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल को मिल गया चिराग पासवान का साथ!

नईदिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में लेटरल एंट्री को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि वह इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं। ऐसी भर्तियों में आरक्षण के प्रावधान की मांग करते हुए पासवान ने कहा कि वह इस मामले को सरकार के समक्ष उठाएंगे। यह पहली बार था जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के किसी सहयोगी ने सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ बात की।

पासवान ने कहा कि जहां भी सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां हों, वहां आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक-शुबहा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है, वो मेरे लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं और इन मुद्दों को उठाने के लिए मेरे पास मंच है। अपनी पार्टी की तरफ से बोलते हुए, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसपर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम को अब समझ लेना चाहिए कि वह गठबंधन सरकार चला रहे हैं और उन्हें अपने सहयोगियों की राय लेकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। लोकसभा सांसद की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लैटरल एंट्री के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करने के सरकार के कदम को राष्ट्र-विरोधी कदम करार दिए जाने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को यूपीएससी ने 24 केंद्रीय मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक के 45 पदों की लैटरल भर्ती के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित अन्य से आवेदन आमंत्रित किए थे।

काफिला छोड़कर उबर कैब में बैठे राहुल गांधी

- ड्राइवर से गिग वर्कर्स की चुनौतियों पर की चर्चा

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्साह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही कारण है कि वह अलग-अलग लोगों से लकातार मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह एक लोकप्रिय राइड-हेलिंग ऐप के माध्यम से कैब बुक कर रहे हैं और वाहन की अगली सीट पर बैठकर राजधानी भर में यात्रा करते हुए ड्राइवर से अपने दैनिक संघर्षों के बारे में बात कर रहे हैं।

राहुल ने एक्स पर लिखा कि आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम - ये है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा! सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबेर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिल कर देश के कैब ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर की समस्याओं का

जायज़ा लिया। उन्होंने आगे लिखा कि हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुज़ारा तंगी से चल रहा है - न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार। इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोंस नीतियां बना कर न्याय करेंगी - और इंडिया जनबंधन पूरे संघर्ष के साथ इसका देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा।

गांधी ने उपाध्याय को बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कंपनियों को गिग वर्कर्स के लिए पेंशन देने का आदेश दिया है।

जब गांधी ने उपाध्याय से पूछा कि वे क्या बदलाव देखना चाहेंगे, तो उपाध्याय ने ड्राइवरों के लिए कटौतियों के बाद इतनी आय की आवश्यकता पर जोर दिया कि वे अपने घर का खर्च चला सकें, और न्यूनतम वेतन की स्थापना की वकालत की। अगले दिन गांधी ने उपाध्याय के परिवार से एक भोजनालय में मुलाकात की, जहाँ उन्होंने उनसे उनकी चुनौतियों, सपनों और आकांक्षाओं के बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस शासित दो राज्य तेलंगाना और कर्नाटक राइड-हेलिंग ऐप के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स की स्थिति में सुधार के लिए एक कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

जडेजा सहित कई खिलाड़ियों का सीएसके से कटेगा पता

नईदिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रविंद्र

जडेजा को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। पिछले सीजन 11 मैचों में 142.78 की स्ट्राइक रेट से 267 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। रविंद्र जडेजा को चेन्नई ने पिछले सीजन 16 करोड़ में रिटेन किया था।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मेगा ऑक्शन से पहले टीम उन्हें रिलीज कर सकती है। हालांकि, चेन्नई नीलामी के दौरान उन्हें वापस खरीद सकते हैं। ऐसे में टीम के पर्स में पैसे अधिक बच सकते हैं। रविंद्र जडेजा लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं। लेकिन 16 करोड़ में उन्हें रिटेन करना टीम के लिए घाटे का सौदा हो सकता है।

अजिंक्य रहाणे एक और खिलाड़ी हैं जिन्हें सीएसके द्वारा रिलीज़ किया जा सकता है। रहाणे 12 मैचों में केवल 242 रन ही बना पाए, जो पिछले सीज़न के लिए उम्मीद से कम था। इस खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से रिलीज़ किया जा सकता है।

कीवी बल्लेबाज रचिन रविंद्र भी सीएसके की संभावित रिलीज लिस्ट में शामिल हैं। रविंद्र ने 10 मैचों में 160.86 की स्ट्राइक रेट से 222 रन बनाए हैं। यह फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सीएसके उन्हें डेरिल मिशेल पर तरजीह देती है या नहीं। डेरिल मिशेल को पिछले सीजन टीम ने 14 करोड़ में खरीदा था।

तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह सीएसके की रिलीज लिस्ट में एक और नाम हो सकता है। सिंह ने चार मैचों में पांच विकेट लिए, लेकिन 10 की इकॉनमी रेट के साथ कुछ महंगे रहे। दीपक चाहर को भी रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है। चाहर ने आईपीएल 2024 के दौरान आठ मैचों में पांच विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 8.59 रहा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 378 अंक मजबूत हुआ निफ्टी 24,700 के करीब

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट में बड़े पैमाने पर मजबूत रुख के बीच बैंकिंग, फाइनैंशियल और ऑटो शेयरों में मजबूत खरीदारी के कारण बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को चढ़ गए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 378.18 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त लेकर 80,802.86 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 80,517.95 और 80,942.96 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 126.20 अंक या 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,698.85 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,607.20 और 24,734.30 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनैंस और कोटक बैंक सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे। इसके अलावा, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एनटीपीसी के शेयर भी लाभ में रहे।

मलयेशियाई कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत-मलयेशिया सीईओ फोरम की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोमवार को बैठक को संबोधित करते ऐसे कई क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जहां दोनों देश अधिक गहराई से सहयोग कर सकते हैं, जिससेउनके व्यापार और व्यावसायिक संबंधों का विस्तार हो सकता है। फोरम ने दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं को आपसी अवसरों का पता लगाने और विकास को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए कए मंच प्रदान किया। गोयल ने भारत और मलयेशिया में व्यवसायों के बीच अधिक तालमेल की संभावना पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स और स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में।

76 हजार 293 करोड़ की बकाया वसूली में सेबी नाकाम

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी विभिन्न प्रयासों के बावजूद 76,293 करोड़ की बकाया राशि को वसूलने में नाकाम रहा है। यह रकम पिछले साल की तुलना में चार फीसदी बढ़ गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2023-24 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा, 31 मार्च, 2024 तक वसूली में मुश्किल (डीटीआर) के रूप में 807 मामलों की पहचान की गई है। इन पर 76,293 करोड़ बकाया है। 2023 में 73,287 करोड़ के 692 मामलों की पहचान की गई थी। इन 807 मामलों में 36 राज्य की अदालतों, एनसीएलटी व एनसीएलएटी में चल रही कार्यवाही के कारण लंबित हैं। इन मामलों 12,199 करोड़ की राशि शामिल हैं। इसके अलावा, 60 मामले कोर्ट की ओर से गठित समितियों के समक्ष हैं, जिनमें 59,970 करोड़ शामिल हैं। सेबी का कहना है कि बकाया राशि की वसूली कठिन है। यह ऐसी राशि है, जिनकी वसूली सुधार के सभी उपायों को लागू करने के बाद भी नहीं हो पाई है।

वेदांता ने ओएफएस से 3200 करोड़ रुपए जुटाए

नईदिल्ली। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के शेयरों की बिक्री पेशकश से करीब 3,200 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। सूत्रों ने कहा कि वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयरों की बिक्री पेशकश (ह्वस्र) को खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। सूत्रों ने कहा कि इस बिक्री पेशकश से वेदांता को करीब 3,200 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। वेदांता ओएफएस से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल अपने बही-खाते को दुरुस्त करने और अपनी विस्तार परियोजनाओं में निवेश के लिए करेगी। पिछले महीने पात्र संस्थागत आवंटन से जुटाई गई 8,500 करोड़ रुपये की राशि को मिलाकर वेदांता समूह और एचजेडएल दोनों का कर्ज कम करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान, कृषि को ट्रांसफॉर्म करना समय की मांग

डॉ. जयंती लाल भण्डारी

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक आर्थिक संगठनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत में कृषि सेक्टर में सुधार और ग्रामीण खपत में वृद्धि के मद्देनजर भारत की विकास दर के अनुमान बढ़ाए जा रहे हैं।

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीपी) के द्वारा जारी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के विकास दर अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 फीसदी, ओईसीडी ने 6.2 से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 6.3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा फिच ने 7 से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार को इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है।

बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रयशक्ति बढ़ी है।

ऐसे में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। कृषि संबंधी

संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है और गांवों में उपभोक्ता सामानों की खरीदारी भी उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है।

हाल ही में 12 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.54 फीसदी रह गई है, जबकि जून 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.08 प्रतिशत थी।

खुदरा महंगाई दर पिछले 5 वर्षों के सबसे कम ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से भी नीचे है। निस्संदेह इस समय किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल उभरकर दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी।

इससे महंगाई से भी बचाव होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। इस बजट के माध्यम से कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों पर ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को नियंत्रित रखने के कारगर प्रयासों की डगर पर लगातार आगे बढ़ना होगा।

भाजपा सदस्यता अभियानः राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बोले-

भारत को विकसित देश बनाने की यात्रा में बने सहभागी

रायपुर. भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी सदस्यता अभियान के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को राजधानी स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक/कार्यशाला आयोजित की गई. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने उपस्थित पदाधिकारियों औरजनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया.

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि यह संगठन पर्व की शुरुआत है और इसमें पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाना है. आज हमारे लिए वातावरण अनुकूल है. देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में तीसरी बार सरकार बनी है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है. पिछली सदस्यता समाप्त हो गई है,अब फिर से सभी को सदस्य बनाकर,भारत के विकसित देश बनने की यात्रा में सहभागी बनाना है. देश की आजादी के बाद जो नीतियां थीं, वह देश के अनुकूल नहीं थी. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी कश्मीर के मुद्दे पर शहीद हो गए. यह ध्यान रखें कि जनसंघ का गठन जिस भाव से हुआ वह सभी के बीच पहुंचे.

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सिंह ने कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ताओं की तपस्या और त्याग के बल पर ही सबसे बड़ी पार्टी बनी है. हमने कभी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया. धारा 370 खत्म करके , लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हमने अपनी इसी वैचारिक प्रतिबध्दता का परिचय दिया है. एक पर्व की तरह हम इस सदस्यता अभियान को मनाएं. सिंह ने 2014, 2019 से लेकर अब तक के सदस्यता अभियान की जानकारी देकर बताया कि पार्टी की सदस्यता ऑनलाइन इस बार भी होगी. सदस्यता के लिए जाते समय साहित्य के साथ सरकार की उपलब्धियां बताना है और पार्टी के उत्कृष्ट चाल, चरित्र, चेहरे के बारे में भी बताएं.

ऑनलाईन सदस्यता के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि जिन सदस्यों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे मिस्ड कॉल करेंगे. इसके बाद उनके पास लिंक आएगा जिसे अन्य सदस्य के स्मार्ट फोन पर भेजकर सदस्यता ले सकेंगे. सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान के लिए 31 अगस्त तक बूथ स्तर पर बैठकें करनी है. सदस्यता के विभिन्न चरणों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यता विस्तारक अब सदस्यता सहयोगी होंगे. सभी बूथों पर सांसदों, विधायकों, जि.पं. अध्यक्षों, महापौरों को भी लक्ष्य दिए जाएंगे और सभी बूथ स्तर तक जाएंगे. प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 विशिष्ट जनों को सदस्य बनाना है. अटल के जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त 20 सदस्य बनाना है. इसके बाद सक्रिय सदस्यता के लिए काम होगा. सक्रिय सदस्य के संबंध में प्रदेश और जिला अध्यक्ष निर्णय लेंगे.

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि सभी पार्टी कार्यालयों में 'सदस्यता अभियान संगठन पर्व' की जानकारी अलग अलग माध्यमों से दे, सोशल मीडिया में पोस्ट करें, इससे वातावरण बनेगा तो सदस्य संख्या में अप्रत्याशित वृध्दि होगी. इस संबंध में किसी भी बिन्दु पर केन्द्रीय कार्यालय में हेल्प सेंटर से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकेंगे. सिंह ने कहा कि सदस्यता मिस कॉल, नमो एप और क्यूआर कोड से ली जाएगी. इसमें अपना पूरा लोकेशन और पता अवश्य देना होगा. जिन क्षेत्रों में नेटवर्क बिल्कुल नही है, वहां प्रादेशिक टीम सुनिश्चित करेगी कि वहां पेपर सदस्यता ही स्वीकार होगी.

समाज के सभी वर्गों तक पहुचेंगे,जहां कमजोर वहां देंगे विशेष ध्यान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय-

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के रूप में मनाना है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा सफल रही है और प्रदेश औरकेन्द्र में भाजपा की सरकार बनी है. सभी कार्यकर्ताओं को समय देकर इस अभियान को सफल बनाना है. सदस्यता अभियान में हमें उन क्षेत्रों पर फोकस करना है जहां हम कमजोर रहते है और सभी समाज औरसभी वर्गों का समर्थन हासिल करना है. इस दौरान प्रदेश और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाए और साथ ही पार्टी के भावी कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में बताया जाए. साय ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार के दोषी सीखचों के पीछे जा रहे है. इस तरह भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वासपूर्ण वातावरण का लाभ उठाकर हम सदस्यता अभियान को सफल बनाए.

भाजपा ही एकमात्र कार्यक्रम आधारित राजनीतिक दल है- किरण सिंह देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज यह कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है. सदस्यता अभियान की इस कार्यशाला में सदस्यता के विभिन्न चरणों का कुशल सम्पादन करने के संबंध में हम सब सक्रिय हो. हमारा सबसे प्रमुख कार्यक्रम सदस्यता अभियान है. भाजपा ही एकमात्र कार्यक्रम आधारित राजनीतिक दल है. लेकिन तेजी से काम करें. पिछला सदस्यता अभियान 6 माह तक चला था लेकिन इस बार दो-ढाई माह की अवधि में यह कार्य पूर्ण करना है. देव ने कहा कि यह हमारा महत्वपूर्ण कार्य है. और किसी अन्य राजनीतिक दल में इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई देती. इसलिए अब प्राथमिकता के आधार पर सबको सदस्यता अभियान में जुटना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस विकसित भारत का संकल्प व्यक्त किया है, उसमें पार्टी के सभी सदस्यों की महती भूमिका है, इसलिए सभी कार्यकर्ता अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करके पार्टी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाना है.

बूथ स्तर तक प्रवास करके सदस्यता अभियान को पूर्ण करना है- जम्वाल

बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि कोरोना, चुनाव व्यस्तता के चलते इस बार 10 साल बाद हमें संगठन पर्व मनाने का अवसर मिला है. सभी कार्यकर्ता 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अपने लक्ष्य को अर्जित करें, इसके लिए हमें संगठन पर्व को अपनी प्राथमिकता में रखना है. इस बार के सदस्यता अभियान में एकदम सटीक डाटा मिले, इसके लिए बूथ स्तर तक प्रवास करके सदस्यता अभियान को पूर्ण करना है. भाजपा के 6 बार प्रधानमंत्री देश में रहे और भाजपा मजबूत पार्टी बनकर उभरी है. भाजपा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अग्रणी देश के रूप में भारत खड़ा है. इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की लगन और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना की अहम भूमिका रही है. हम सबकों अजेय भारत की कल्पना को साकार करने के लिए पार्टी को सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी बनाना होगा.

2025 में हमारे वैचारिक अधिष्ठान का शताब्दी वर्ष है-पवन साय

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आगामी कार्यक्रमों की रुपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें. यह लक्ष्य जब संगठन औरसत्ता के सामने होता है, तब वह आगे बढ़ता है. 2025 में हमारे वैचारिक अधिष्ठान का शताब्दी वर्ष है. संगठनात्मक दृष्टि से सदस्यता अभियान हमें दो माह में पूर्ण करना है. 1 सितंबर को प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है. ऐसे भी कई बूथ है जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्यादा ध्यान देना है ताकि पार्टी को नुकसान न हो और पार्टी के वैचारिक धरातल को हमें मजबूत बनाना है. इस निमित्त सभी जिलों की बैठक 22 से 24 अगस्त तक होगी. 1 सितंबर को प्रधानमंत्री दिल्ली से सदस्यता ग्रहण कर अभियान शुरु करेंगे. अगले दिन 2 सितंबर को प्रदेश और 3 सितंबर को जिला मुख्यालयों में और फिर मंडल मुख्यालयों तक समारोह पूर्वक सदस्यता अभियान की शुरूआत होगी. शक्तिकेन्द्र संयोजक, सह संयोजक औरसदस्यता सहयोगी मिलकर 30 अगस्त तक अभियान की संरचना पूर्ण करेंगे. साय ने बताया कि जन प्रतिनिधियों को भी सदस्यता का लक्ष्य दिया गया है ताकि सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और सभी लोगों को 50 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया. कागजी और ऑनलाइन सदस्यता का अपडेट केन्द्र तक जाएगा इसलिए सदस्यता फार्म और ऑनलाइन डाटा अपडेट रखना है. सांसदों और विधायकों जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौरों को व्यक्तिगत रूप से सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है. विषय की सुगम जानकारी के लिए जिला और मंडल स्तर पर भी कार्यशाला होगी जिसमें सभी प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. साय ने सदस्यता अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया. सदस्यता के लिए फार्म अपडेट करने और ऑनलाइन अपडेट करने के लिए दायित्व दिया जाएगा.

सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की कड़ियों पर ध्यान दें. 2014 में सदस्यता अभियान में 22 लाख सदस्य बनाए गए और 2019 में 9 लाख सदस्य बनाए गए थे. कुल 31.40 लाख सदस्यों को पुनः सदस्यता दिलाई जाएगी. चुनावी रणनीति की तरह ही सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. इस निमित्त जिला, मंडल स्तर पर भी कार्यशालाएं होंगीं और मंडल, बूथ प्रभारी नियुक्त होंगे.

शराब घोटाले के सभी आरोपियों की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं पर आज फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द कर दिया है. उच्च न्यायालय ने माना है कि सबूतों के आधार पर ही ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है.

शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निदेश पुरोहित, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कराने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने विगत 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है.

उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की थी. राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने जिरह किया था. उच्च न्यायालय में छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्ल्यू-एसीबी के खिलाफ दायर थीं. इन याचिकाओं में शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा पुनः की जा रही कार्यवाही और ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्हें खारिज करने की याचना की गई थी.

इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा के मुताबिक, कांग्रेस सरकार में अनवर ढेबर ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए एपी त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का एमडी नियुक्त कराया था. इसके बाद अधिकारी, कारोबारी और राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया.

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है. दर्ज एफआईआर में दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है. ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था. एसीबी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है. शराब घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने सबसे पहले मई के शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया. ईडी के मुताबिक अनवर ढेबर ने साल 2019 से 2022 तक दो हजार करोड़ रुपए का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया. इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया. ईडी की ओर से यह बड़ी बात कही गई कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने राजनीतिक आकाओं को दी है.

जनसम्पर्क की छायाचित्र प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केन्द्र

रायपुर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग टाउन हॉल पहुंच रहे हैं। यहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी में स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक

है।

प्रदर्शनी देखने के लिए यहां प्रतिदिन आने वाले स्कूली विद्यार्थियों के मध्य क्विज प्रतियोगिता एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन तथा विजयी प्रतिभागियों को तत्काल मिलने वाले पुरस्कार से प्रदर्शनी को लेकर स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं में रूझान बढ़ा है। क्विज प्रतियोगिता एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए इस क्षेत्र के अनुभवी अनंत विकास अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कूली विद्यार्थियों के मध्य आयोजित उक्त दोनों प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पुरातत्व पर्यटन, संस्कृति, लोक कला, खेती-किसानी सहित अन्य विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

21 को भारत बंद का आह्वान, चेंबर ने नहीं दिया समर्थन

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को कई दलित संगठनों और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का समर्थन प्राप्त है। हालांकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ने भारत बंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा है कि एससी/एसटी आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को कई संगठन आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने वाला मान रहे हैं और इसीलिए वे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत बंद के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ निजी दफ्तर भी बंद रह सकते हैं। अस्पताल, एम्बुलेंस जैसी सभी आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।

हरियाणा-जम्मू विस चुनाव में छग के 12 अधिकारी बनाए गए ऑब्जर्वर

रायपुर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर बनाया है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 9 आईएएस अफसरों जिनमें हिमशिखर गुप्ता, राजेश सिंह राणा, नरेंद्र कुमार दुग्गा, भीम सिंह, डॉ. प्रियंका शुक्ला, जय प्रकाश मौर्या, संजीव कुमार झा, विनित नंदनवार और ऋतुराज रघुवंशी का नाम शामिल है। इसके अलावातीन आईपीएस अफसरों प्रशांत कुमार अग्रवाल, अभिषेक मीणा, उदय किरण को ऑब्जर्वर के बनाकर यहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। बतादें कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में (18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर) विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा में एक अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना एक साथ चार अक्टूबर को होंगे।

जल और संपत्ति कर भुगतान करने वालों को मिलेगा निःशुल्क कनेक्शन

रायपुर। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आज महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई. इस बैठक में मुख्य एजेंडा अमृत मिशन के तहत अतिरिक्त नल कनेक्शन देने पर चर्चा हुई. वहीं बैठक में जल और संपत्ति कर देने वाले हितग्राहियों का परीक्षण कर निःशुल्क नल कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है और बचे हितग्राहियों को नियमानुसार शुल्क लेकर ही नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे. एमआईसी की बैठक लगभग 1 घंटे तक चली जिसमें एमआईसी सदस्यों सहित उपायुक्त विनोद पांडेय, उपायुक्त राजेंद्र गुप्ता, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित जोन आयुक्त मौजूद रहे. आज के बैठक में मैसूर और बंगलौर के अध्ययन भ्रमण से सीखे गए विषयों को रायपुर में लागू किए जाने पर भी चर्चा होनी थी. हालांकि निगम आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण इन विषयों पर आज चर्चा नहीं हो सकी. इसमें ओपन प्रापर्टी के टैक्स का वन टाइम सेटलमेंट ,बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी अस्पतालों में पहली बेटी के जन्म पर 20 हजार नगर निगम द्वारा जमा कराने साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए नाश्ता उपलब्ध कराना शामिल था. महापौर ढेबर का कहना है कि निगम का राजस्व निरंतर बढ़त में है और अब 400 करोड़ राजस्व वसूली पहुंचने वाली है. ऐसे में इतने पैसों का निगम क्या करेगी? हमारी इच्छा शक्ति है इन योजनाओं को सफल बनाना जो हम करके रहेंगे. महापौर ढेबर की योजनाओं पर विपक्ष की

राजेश सिंह राणा व शिखा राजदूत प्रभारी सचिव नियुक्ति

रायपुर। राज्य सरकार ने दो जिलों के प्रभारी सचिव बदले हैं। 2008 बैच के आईएएस राजेश सिंह राणा को सारंगढ़ बिलाईगढ़ का प्रभारी सचिव बनाया गया है, तो वहीं शिखा राजपूत तिवारी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की प्रभारी सचिव होगी। जीएडी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रभारी सचिव को महीने में कम से कम एक बार जिले का भ्रमण कर समीक्षा करनी होगी। भ्रमण से संबंधित टीप चीफ सेकरेट्री को भेजना होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 1 जुलाई को प्रभारी सचिव की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। उस आदेश में सारंगढ़ बिलाईगढ़ का प्रभारी सचिव 2005 बैच के नीलम नामदेव एक्का को बनाया गया था। वहीं खैरागढ़ छुईखदान-गंडई का प्रभारी सचिव महादेव कांवरे को बनाया गया था। पिछले दिनों हुई प्रशासनिक फेरबदल में 2008 बैच के द्वय महादेव कांवरे को रायपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है। वहीं 2005 बैच के द्वय नीलम नामदेव एक्का को बिलासपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है। जिसकी वजह से प्रभारी सचिव के जिलों में फेरबदल किया गया है।

दो आईएएस को मिला अतिरिक्त प्रभार - राज्य शासन ने दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वार जारी आदेश में अभिजीत सिंह (संयुक्त सचिव गृह-जेल विभाग) को चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मथुरा में जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि पर बनेगा भव्य मंदिर

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में नव निर्मित देश के सबसे बड़े राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सिद्धार्थ स्वामी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सिद्धार्थ स्वामी के प्रयासों से देश के सबसे बड़े और भव्य राधा रास बिहारी मंदिर का निर्माण हो पाया। उन्होंने यह भी कहा कि, पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से पहले सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा राम मंदिर वीआईपी रोड रायपुर में बना। अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनने से पूर्व छत्तीसगढ़ में भगवान रास बिहारी का मंदिर बन कर तैयार हो चुका है। जो बताता है कि, जल्द ही मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि, इस्कॉन केवल मंदिर ही नही बनता, बल्कि इसके माध्यम से मानव सेवा का कार्य भी करता है और आशा करता हूं कि इस्कॉन इस मंदिर के माध्यम से आदिवासी समाज की स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में की मदद करेगा।

राइस माफियाओं पर गिरेगी गाज...

...अब कस्टम मीलिंग घोटाले पर एक्शन लेगी साय सरकार

रायपुर । शराब में एफएल-10 समाप्त कर लाइसेंसी सिस्टम को खत्म करने वाली छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अब कस्टम मीलिंग घोटाले में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस मामले में प्रदेश के राइस माफियाओं को बड़ा झटका देने की तैयारी है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है, जिसमें अब तक मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी और स्पेशल सेक्रेटरी फूड मनोज सोनी और राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

ईडी के प्रतिवेदन के अनुसार, राइस मिलरों को फायदा पहुंचाने

के लिए मीलिंग प्रोत्साहन राशि को 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया था। इस वृद्धि के पीछे एक सोची-समझी साजिश थी, जिसके तहत राइस माफियाओं से यह सौदा हुआ था कि 120 रुपए में से 40 रुपए कैश में लौटा दिए जाएंगे। 2023-24 में छत्तीसगढ़ में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, जिसके मीलिंग प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। ईडी के अनुसार, इसमें से 175 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव सरकार ने इस घोटाले पर कड़ी नजर डालते हुए कार्रवाई शुरू की है। दूसरी किस्त के रूप में जारी 40 रुपए प्रति क्विंटल वाली राशि में भी राइस मिलरों को लाभ पहुंचाया गया, लेकिन अब सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठा रही है। अनुमान है कि दूसरी किस्त से 214 करोड़ रुपए राइस मिलरों की जेब में चले गए हैं।

ईडी के प्रतिवेदन के मुताबिक, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का फायदा सीधे राइस मिलरों को हुआ है। 2023-24 में 124 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जिससे मिलिंग प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1640 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार ने अब इस पूरे घोटाले पर लगाम लगाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही कस्टम मीलिंग के खेल पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मीलिंग चार्ज में हुई 80 रुपए की वृद्धि को कम करने का विचार किया जा रहा है, जिससे राज्य के खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अफसरों के अनुसार, मीलिंग चार्ज अगर 70 रुपए भी किया जाता है, तो सरकार को सात सौ से आठ सौ करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

छत्तीसगढ़ की छात्रा ने राष्ट्रपति से भेंट कर किया संवाद, चेतना ने कहा- ये पल मेरे लिए ऐतिहासिक

गरियाबंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रक्षाबंधन के अवसर पर भेंट-मुलाक़ात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के पांच जिलों से शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने भेंट की। दिल्ली गई टीम का शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देवभोग की कक्षा 9वीं की छात्रा चेतना सोना ने प्रतिनिधित्व किया। छात्राओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और संवाद किया। चेतना सोना ने कहा कि यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक रहे। राष्ट्रपति ने प्रदेश की बेटियों

का हाल जाना। केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से दी जा रही शिक्षा में गुणवत्ता को भी जानने की कोशिश की। छात्राओं से बेहतर जवाब सुन राष्ट्रपति ने संतुष्टि जाहिर की। जिज्ञासु छात्राओं के सवाल के जवाब भी राष्ट्रपति ने सहजता से दिया। भेंट मुलाकात के बाद छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल में शामिल चेतना सोना ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के कलाई में राखी बांधी। राष्ट्रपति से भेंट के बाद हुई चर्चा में चेतना ने बताया कि यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक थे। चेतना ने पहली बार की हवाई यात्रा के अनुभव को भी साझा किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.